

है।
थी,
था।
51
कर
एक
पने
में
हुई।
भूमि
नसे
7.5
न्य



नई दिल्ली, शुक्रवार
18 अप्रैल 2025

नेशनल प्रेस टाइम्स

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

नई दिल्ली। (राष्ट्रीय संस्करण)

वर्ष : 11, अंक : 49

www.nationalpresstimes.com

पृष्ठ : 10

मूल्य : 05 रुपये

RNI No : UPHIN/2015/64579

मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर बोला विदेश मंत्रालय

बेल्जियम के संपर्क में है भारत पाकिस्तान पीओके खाली करे

नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को कहा कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत सरकार के औपचारिक अनुरोध के आधार पर शनिवार को चोकसी को बेल्जियम के एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया। विदेश मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक प्रेसवार्ता में अमेरिका, चीन, रूस, बांग्लादेश से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं। पढ़ें...

भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, 'हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। हम उसके प्रत्यर्पण पर बेल्जियम पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।' बता दें कि, 13,500 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को मेहुल चोकसी की तलाश है।

'वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान की पहचान'- इस दौरान 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले, लेकिन वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। राणा का प्रत्यर्पण



पाकिस्तान को याद दिलाता है कि उसे मुंबई हमलों के अन्य अपराधियों को भी न्याय के कटघरे में लाना होगा, जिन्हें वह अभी भी बचा रहा है'।

जेडी वेंस की भारत यात्रा, द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा- वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा पर रणधीर जायसवाल ने कहा, 'अपनी यात्रा के दौरान वे

प्रधानमंत्री से मिलेंगे और भारत और अमेरिका के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।' अमेरिकी टैरिफ पर उन्होंने कहा, 'हम अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे हैं ताकि द्विपक्षीय व्यापार समझौता किया जा सके'।

क्या रूस के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी?- इस दौरान विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी को रूस से मिल निमंत्रण पर कहा, 'प्रधानमंत्री को रूसी राष्ट्रपति से निमंत्रण मिला है और जैसा कि मैंने आपको बताया, विजय दिवस समारोह में हमारी भागीदारी की घोषणा की जाएगी'।

कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन से सीधी हवाई सेवा- इस दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम जल्द ही कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जनता के लिए एक नोटिस जारी करेंगे। यात्रा जल्द ही फिर से शुरू होने की संभावना है।' वहीं भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवाओं पर रणधीर जायसवाल ने कहा, 'सैद्धांतिक रूप से, दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उड़ान संचालन फिर से शुरू होगा। दोनों पक्षों की तकनीकी टीमें उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं पर विचार कर रही हैं'।

शेष पेज 2 पर

ऐसी कल्पना नहीं की थी, जहां जज कानून बनाएंगे'

सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर बोले उपराष्ट्रपति धनखड़

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे। वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता'।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत में ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी, जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे और कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और 'सुपर संसद' के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर विधेयक पर फैसला लेने की समयसीमा की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, जब राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने को कहा जा रहा है।

'जज सुपर संसद की तरह काम करेंगे'-राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम की संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'एक हालिया फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें इसे लेकर बेहद



संवेदनशील होने की जरूरत है। हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी, जहां राष्ट्रपति को तय समय में फैसला लेने के लिए कहा जाएगा और अगर वे फैसला नहीं लेंगे तो कानून बन जाएगा।' उपराष्ट्रपति ने कहा कि 'अब जज विधायी चीजों पर फैसला करेंगे। वे ही कार्यकारी जिम्मेदारी निभाएंगे और सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होगी क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू ही नहीं होता'।

'ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी' धनखड़ ने हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 'अपने जीवन में मैंने ऐसे दिन की कल्पना नहीं की थी'।

शेष पेज 2 पर

स्टालिन ने किया विरोध तो फडणवीस ने अपनाया, महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिन्दी होगी अनिवार्य



नई दिल्ली। मराठी या अंग्रेजी के अलावा अन्य शिक्षण माध्यम वाले स्कूलों के लिए मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य हो जाएंगे, जबकि संबंधित शिक्षण माध्यम तीसरी भाषा के रूप में काम करेगा। जीआर ने एनईपी के चार-चरणीय रोलआउट की रूपरेखा तैयार की है, जिसकी शुरुआत 2025-26 में कक्षा 1 से होगी।

भाषा विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के

लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पेश किया जाएगा। बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के माध्यम से निर्णय सार्वजनिक किया गया। अभी तक, तीन-भाषा सूत्र केवल माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लागू किया गया है। इस कदम के साथ, यह सूत्र अब मराठी-माध्यम और अंग्रेजी-माध्यम विद्यालयों में भाषाई ढांचे को नया रूप देने के उद्देश्य से प्राथमिक शिक्षा तक विस्तारित होगा।

शेष पेज 2 पर

वक्फ कानून पर 'सुप्रीम' सुनवाई:

सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय,
अगली तारीख तक यथास्थिति बनी रहेगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बीते दिन कोर्ट ने मामले की करीब दो घंटे सुनवाई की थी। इस दौरान पीठ ने अंतरिम रोक को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया था। अब जानिए सर्वोच्च न्यायालय में आज क्या-क्या हुआ...

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ से केंद्र की मांग पर सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया।



सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक 'उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ' या 'दस्तावेजों की ओर से वक्फ' संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 के अधिनियम के तहत हुआ है, तो उन संपत्तियों को 5 मई को अगली सुनवाई तक गैर-अधिसूचित नहीं किया जा सकता। इसके बाद कोर्ट ने

मामले की अगली तारीख 5 मई तय की। सरकार की दलील-सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। सरकार को लाखों-लाखों प्रतिनिधि मिले, गांव-गांव वक्फ में शामिल किए गए। इतनी सारी जमीनों पर वक्फ का दावा किया जाता है। इसे कानून का हिस्सा माना जाता है। अंतरिम रोक की राय पर

मेहता ने कहा कि कानून पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा। उन्होंने अदालत के सामने कुछ दस्तावेजों के साथ प्रारंभिक जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि इस दौरान बोर्ड या काउंसिल की कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिस पर इस तरह से विचार किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, अदालत ने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं और इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। वह नहीं चाहता कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव हो।

शेष पेज 2 पर

सोनिया-राहुल के बचाव में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, खरगो की अध्यक्षता में अहम बैठक



नई दिल्ली। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर दाखिल आरोपपत्र के बचाव में अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को एक अहम रणनीतिक बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे।

कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बचाव में अपनी तैयारी तेज

कर दी है। इसके लिए पार्टी ने गुरुवार को हेराल्ड मामले के विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन की रणनीति तैयार करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी भवन में होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, इसमें पार्टी के सभी महासचिव, प्रदेश प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे।

शेष पेज 2 पर

बिहार में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन?

सामने आया सी वोटर का चौंकाने वाला सर्वे

पटना। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं और अब तक लगातार 10 साल से सीएम हैं। बीच के कुछ महीनों के छोड़ दे तो उससे पहले भी वह सीएम रहे हैं। नीतीश लगातार बिहार का नेतृत्व 2005 से कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में अब लगभग छह महीने बाकी हैं। लेकिन चुनावी रुझानों पर नजर रखने वाले सी-वोटर द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि जेडी(यू) नेता नीतीश कुमार अगले बिहार चुनाव के लिए शीर्ष विकल्प नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले



व्यक्ति हैं और अब तक लगातार 10 साल से सीएम हैं। बीच के कुछ महीनों के छोड़ दे तो उससे पहले भी वह सीएम रहे हैं। नीतीश लगातार बिहार का नेतृत्व 2005 से कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए सीएम पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि, अब सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार तीसरे स्थान पर हैं, तो बिहार

के सीएम पद के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार कौन है? सी-वोटर सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव अगले बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। इस बीच, विश्लेषक से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया।

शेष पेज 2 पर

ईडी के फेर

ईडी के फेर में फंसे राहुल-सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा

और कितने मामलों में घिरा है गांधी परिवार?

नई दिल्ली। गांधी परिवार के सदस्यों पर कितने मामले दर्ज हैं? उन्हें कितने मामलों में आरोपी बनाया गया है? इसके अलावा राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी पर अलग-अलग कितने केस हुए हैं? इन मामलों की मौजूदा स्थिति क्या है? आइये जानते हैं...

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपपत्र में इन पर एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) के अंतर्गत आने वाली 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति को हड़पने का आरोप है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी जमीन के लेनदेन से जुड़े मामलों में पूछताछ कर रही है।



हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार के सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर कुल मिलाकर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिन पर कार्रवाई अलग-अलग चरण में जारी है।

आखिर गांधी परिवार के सदस्यों पर कितने मामले दर्ज हैं? उन्हें कितने-

किन मामलों में आरोपी बनाया गया है? इसके अलावा राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी पर अलग-अलग कितने केस हुए हैं? इन मामलों की मौजूदा स्थिति क्या है? आइये जानते हैं... कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2024 को लोकसभा चुनाव में दिए गए चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उन पर कुल 18 मामले दर्ज हैं।

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी दो अन्य मामलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हैं। यानी उनके ऊपर चल रहे मामलों की संख्या 20 के ऊपर पहुंच गई है।

किस-किस मामले में घिरे हैं राहुल गांधी?

राहुल पर जिन मामलों में केस दर्ज हुए हैं, उनमें पॉक्सो एक्स से लेकर मानहानि तक की धाराओं में मामले हैं। आइये विस्तार से जानें उन पर दर्ज मामलों के बारे में...

1. मानहानि के केस: 15

राहुल गांधी पर मानहानि के मामलों में कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक मामले दर्ज हैं। इनमें से एक मामले में वे दोषी भी करार दिए जा चुके हैं। वहीं, बाकी 14 मामले कोर्ट में अलग-अलग दौर में हैं। इनमें कुछ प्रमुख केस हैं...शेष पेज 2 पर

पंचायत चुनावों के संदर्भ में असम के विश्वनाथ में 2232 मतदान पीटासीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पहला चरण किया गया आयोजित

प्रथम चरण में कुल 558 पीटासीन अधिकारियों और पूलिंग अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित।

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो असम: असम में होने जा रहे आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर विश्वनाथ जिले के विश्वनाथ और बिहाली विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 558 जिला परिषदों के चुनाव के लिए कुल 2232 पुरुष एवं महिला अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रथम चरण में आयोजित इस प्रशिक्षण में 558 पीटासीन अधिकारियों तथा

558 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पूलिंग अधिकारियों को निर्वाचन के जरूरी विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। विश्वनाथ कॉलेज में सुबह 10 बजे से आयोजित इस चुनाव प्रशिक्षण में 22 मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया और चुनाव में बलेट पेपर के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पंचायत चुनाव में विश्वनाथ



जिले के विश्वनाथ और बिहाली विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आठ जिला परिषद क्षेत्रों में महिला अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वोट डालने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इसी के अनुरूप आज के प्रशिक्षण में

60 महिला पीटासीन अधिकारियों तथा 60 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मतदान अधिकारियों को भी आगामी चुनाव में मतदान करने का प्रशिक्षण दिया गया। आज के प्रशिक्षण में विश्वनाथ विधानसभा क्षेत्र के चार जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए असम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षक और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त सचिव अनुजा भुइयां ने

चुनाव प्रशिक्षण में भाग लिया और प्रशिक्षण का जायजा लिया। इसी तरह विश्वनाथ के जिला आयुक्त मुनींद्र नाथ नाटे ने भी प्रशिक्षण में भाग लिया और चुनाव प्रशिक्षण का जायजा लिया। अतिरिक्त जिला आयुक्त राकेश डेका, विश्वनाथ के व्यक्तिगत और प्रशिक्षण निर्वाचन प्रकोष्ठ के अधिकारी और कर्मचारी भी आज प्रशिक्षण के पहले चरण में उपस्थित थे।

असम और मिजोरम सीमा विवाद पर 25 अप्रैल को असम के गुवाहाटी शहर में बैठक

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो, असम : असम और मिजोरम के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 24 अप्रैल को असम के गुवाहाटी में मिजोरम का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आ रहे हैं। यह बैठक 25 अप्रैल को होगी जिसमें अधिकारियों के स्तर पर बातचीत कर आगामी मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए प्रारूप और प्रक्रिया तय की जाएगी। बैठक में असम की ओर से

सीमा संरक्षण विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी और मिजोरम की ओर से गृह सचिव वनलालमाविया शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले पिछले साल 9 अगस्त को मिजोरम के अइजॉल शहर में चौथे दौर की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें दोनों राज्यों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई थी। असम की सीमा तीन जिलों, कछार, करीमगंज और हैलाकांडी –के जरिए मिजोरम के आइजॉल, कोलासिब और मामित जिलों से लगती है। विवाद का मूल कारण 1875 और 1933 की दो अलग-अलग ब्रिटिश कालीन सीमांकन रेखाएं हैं। दोनों राज्य अलग-अलग सीमाओं को वैध मानते हैं और जमीन पर कोई स्पष्ट सीमांकन अब तक नहीं हुआ है। जिसके कारण यह विवाद काफी समय से चलता आ रहा है और इसे हल करने के उद्देश्य से ही यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

एम्स-सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों में मरीजों की बढ़ेगी परेशानी, आधे डॉक्टर ही करेंगे इलाज, जाने वजह

नई दिल्ली। डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों को उसकी स्थिति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टरों की छुट्टी के समय चिकित्सा सुविधा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मरीजों को उसकी स्थिति के आधार पर तारीख दी जाएगी।

एम्स, सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया, लेडी हार्डिंग सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों से संबंधित अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों की अगले माह से परेशानी बढ़ सकती है। इन अस्पतालों में मई से जुलाई तक अलग-अलग तारीखों में

आधे डॉक्टर गर्मियों की छुट्टी पर रहेंगे। इस दौरान मरीजों को सर्जरी, ओपीडी, जांच सहित दूसरे चिकित्सा के लिए लंबी तारीख दी जा सकती है।

एम्स के प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार भारद्वाज की ओर से जारी आदेश के तहत एम्स में डॉक्टरों की गर्मियों की छुट्टियां 16 मई से शुरू हो रही हैं जो 15 जुलाई तक चलेगी। आधे डॉक्टरों का पहला सत्र 16 मई से 14 जून तक छुट्टी पर रहेगा। उनके लौटने के बाद दूसरे आधे डॉक्टरों का सत्र 16 जून से 15 जुलाई तक छुट्टी पर

रहेगा। इस दौरान एम्स में आ रहे मरीजों का इलाज प्रभावित न हो इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन से सभी विभाग प्रमुखों को व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है।

वहीं सफदरजंग, डॉ. राम मनोहर लोहिया सहित अन्य अस्पतालों में भी जल्द डॉक्टरों की छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है। केंद्र सरकार के इन चार बड़े अस्पतालों में प्रति दिन 40 से 50 हजार मरीज ओपीडी में इलाज करवाने आते हैं। वहीं हजारों की संख्या में रोजाना सर्जरी होती

है। इसके अलावा हजारों जांच व दूसरे चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।

आपातकालीन मरीज को मिलेगी प्राथमिकता- डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों को उसकी स्थिति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। डॉक्टरों की छुट्टी के समय चिकित्सा सुविधा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में मरीजों को उसकी स्थिति के आधार पर तारीख दी जाएगी। जो मरीज लंबे समय पर रुक सकता है उसे लंबी तारीख दी जा सकती है, जबकि गंभीर मरीजों की सर्जरी व दूसरे जांच जल्द कर दिए जाएंगे। डॉक्टरों

का कहना है कि छुट्टियों के बावजूद गंभीर मरीजों के इलाज को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

एनआईसी में बढ़ेगी इलाज की सुविधा- एम्स के झज्जर स्थिति राष्ट्रीय कैंसर संस्थान (एनआईसी) में इलाज की सुविधा बढ़ाने के लिए 71 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति निकाली है। सबसे ज्यादा आवेदन 11 पद मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए निकाले गए हैं। एनआईसी के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डॉक्टरों की मांग पर इन पदों पर भर्ती की सहमति दी थी।

पेज एक का शेष...

बेल्जियम के संपर्क में है भारत पाकिस्तान पीओके खाली करे दोनों नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों की बैठक हुई है और वे अद्यतन रूपरेखा सहित प्रासंगिक तौर-तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं।'

वक्फ संशोधन अधिनियम पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'वक्फ विधेयक के सभी तत्व भारत का आंतरिक मामला हैं। और आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक में कई समावेशी नीतियों का प्रस्ताव है, ताकि संशोधन विधेयक को अधिक समावेशी, अधिक प्रगतिशील बनाया जा सके और लक्षित लाभार्थियों को अधिक लाभ मिल सके'।

क्वाड का भविष्य उज्ज्वल है- विदेश मंत्रालय-विदेश मंत्रालय ने अपने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, 'क्वाड का भविष्य उज्ज्वल है और क्वाड शिखर सम्मेलन की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इस दौरान अमेरिका-ईरान वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम अमेरिका-ईरान वार्ता को सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं। हम हमेशा ऐसे मुद्दों पर बातचीत और कूटनीति के पक्ष में रहे हैं'।

'बांग्लादेश के साथ सकारात्मक संबंध की उम्मीद'-इस दौरान भारत और बांग्लादेश संबंधों पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि, 'भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। हम एक लोकतांत्रिक, समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। जहां तक व्यापार मुद्दों का सवाल है, पिछले हफ्ते हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में घोषणा की थी।'

ऐसी कल्पना नहीं की थी, जहां जज कानून बनाएंगे'

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति संविधान की सुरक्षा की शपथ लेते हैं। जबकि सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति और जजों को संविधान का पालन करना होता है। हम ऐसी स्थिति नहीं चाहते, जहां राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाएं। आपको सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत संविधान की व्याख्या का अधिकार है और वह भी पांच या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ ही कर सकती है।'

सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय,

अगली तारीख तक यथास्थिति बनी रहेगी

कोर्ट ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, तो हमे यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव न हो।

सरकार को सात दिन का वक्त- सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ-बाय-यूजर शामिल है, को न तो डीनोटिफाई किया जाएगा और न ही कलेक्टर इसे लेकर कोई फैसला लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे। तब तक यथास्थिति बनी रहेगी।

केवल पांच याचिकाओं पर सुनवाई- दूसरी ओर पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कई याचिकाओं पर विचार करना असंभव है। पीठ ने स्पष्ट किया कि वह केवल पांच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जबकि वकीलों से कहा कि वे आपस में तय करें कि कौन बहस करेगा।

बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या-क्या हुआ?-बीते दिन कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। शीर्ष कोर्ट ने अदालतों की ओर से वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने, वक्फ में पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल करने और कलेक्टरों की जांच के दौरान संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। हालांकि, कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई थी। शीर्ष कोर्ट ने इस मुद्दे पर हो रही हिंसा पर चिंता जताई थी। वहीं, केंद्र सरकार ने प्रावधानों पर रोक के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा था कि शीर्ष कोर्ट को कोई भी निर्देश जारी करने से पहले मामले में सुनवाई करनी चाहिए।

इससे पहले बीते दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की पीठ ने कहा था कि हमारा अंतरिम आदेश हिस्सेदारी को संतुलित करेगा। पहला, हम आदेश में कहेंगे कि न्यायालय की ओर से वक्फ घोषित की गई किसी भी संपत्ति को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा, यानी उसे गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, फिर चाहे वह संपत्ति उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ की गई हो या विलेख के जरिए। दूसरा, कलेक्टर

किसी संपत्ति से संबंधित अपनी जांच की कार्यवाही जारी रख सकता है, पर कानून का यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा कि कार्यवाही के दौरान संपत्ति गैर वक्फ मानी जाए। तीसरा, बोर्ड व परिषद में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन अन्य सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए।

सुनवाई के आखिर में पीठ ने अंतरिम आदेश पारित करने का संकेत दिया, लेकिन उसने केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर बृहस्पतिवार को भी विचार करने का फैसला किया। शीर्ष कोर्ट ने प्रस्ताव रखा कि अलग-अलग हाईकोर्ट में वक्फ कानून 1995 को दी गई चुनौती से संबंधित याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर ली जाएं।

प. बंगाल में हिंसा पर जताई थी चिंता-सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में चल रही हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की और कहा, एक बात बहुत परेशान करने वाली है कि हिंसा हो रही है। अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने भी कहा, हिंसा नहीं होनी चाहिए।

बीते दिन केंद्र सरकार से पूछे गए थे कड़े सवाल-सीजेआई खन्ना : क्या 2025 का कानून उपयोग में आने से पहले उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ की गई सभी संपत्तियां अब वक्फ के रूप में अस्तित्व में नहीं रह गई हैं?

मेहता : संपत्तियां रजिस्टर हैं, तो वक्फ ही रहेंगी।

सीजेआई : अंग्रेजों के आने से पहले देश में संपत्ति रजिस्ट्रेशन की सुविधा नहीं थी। अधिकांश मस्जिदें 14वीं और 15वीं सदी की हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का जामा मस्जिद। वे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे?

मेहता : उन्हें अब तक रजिस्ट्रेशन कराने से किसने रोका है?

जस्टिस विश्वनाथन : अगर सरकार ने धारा 3सी लागू कर उस संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया तो क्या होगा? नए कानून के बारे में पीठ ने उठाए थे ये सवाल- क्या उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ की गई सभी संपत्तियां अब वक्फ के रूप में अस्तित्व में नहीं रह गई हैं?

शताब्दियों से मौजूद उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए कैसे कहा जा सकता है? सीजेआई ने जामा मस्जिद का उदाहरण दिया।

क्या यह कहना उचित है कि जब तक सरकार का अधिकृत अधिकारी इस विवाद की जांच पूरी नहीं कर लेता कि यह सरकारी संपत्ति है या नहीं, तब तक किसी संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा?

धारा 2ए प्रावधान न्यायालय के उन निर्णयों को कैसे रद्द कर सकता है जो संपत्तियों को वक्फ घोषित करते हैं?

क्या नए संशोधनों के बाद, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों के अधिकांश सदस्य मुस्लिम होंगे?

सोनिया-राहुल के बचाव में कांग्रेस की बड़ी तैयारी, खरगे की अध्यक्षता में अहम बैठक

मल्लिकार्जुन खरगे करेंगे बैठक की अध्यक्षता-सूत्रों के अनुसार, यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में होगी। इसमें केंद्र सरकार की ओर से पार्टी के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाए जाने के खिलाफ आंदोलन और देशव्यापी विरोध की योजना पर चर्चा होगी। बता दें कि इससे पहले 10 अप्रैल को, कांग्रेस ने ईडी के आरोपपत्र के खिलाफ देशभर में ईडी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के 24, अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

कांग्रेस का आरोप-वहीं बात अब मामले में कांग्रेस के आरोपों की करें तो पार्टी ने कहा कि यह कार्रवाई सरकार की घबराहत और नैतिक दिवालियापन को दर्शाती है। पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब इस बैठक में तय होगा कि कांग्रेस इस मामले में आगे किस तरह से जनता को जोड़ेगी और सरकार के खिलाफ किस स्तर पर आंदोलन करेगी।

क्या है पूरा मामला, समझिए- गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं पर 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। ईडी ने इस मामले में दायर अपने आरोपपत्र में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर एक बनाया है, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर दो बनाया है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुवे और सैम पित्रोदा, दो कंपनियों यंग इंडियन और डोटैक्स मकेंडाइज प्रा. लि. और डोटैक्स से जुड़े सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है, जिसके विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है।

सामने आया सी वोटर का चौंकाने वाला सर्वे

किशोर ने हाल ही में अपनी पार्टी जन सुराज लॉन्च की थी। उन्होंने कहा कि यह पार्टी पहली बार बिहार चुनाव

लड़ेगी और वह भी सभी 243 विधानसभा सीटों पर।

तेजस्वी को 35 प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री पद की रेस में आगे मानते हैं। वहीं, फरवरी में यह आंकड़ा 40 प्रतिशत से ज्यादा था। प्रशांत किशोर फरवरी में 14 प्रतिशत पर थे। लेकिन अब वह 17 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर हैं। नीतीश के पक्ष में अभी सिर्फ 15 प्रतिशत लोग हैं जो फरवरी में लगभग 19 प्रतिशत थे। चौथे नंबर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी 8 से 12 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। बिहार के एक और मंत्री और भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान बिहार के सीएम पद के लिए पांचवें लोकप्रिय उम्मीदवार हैं।

और कितने मामलों में घिरा है गांधी परिवार?

2014: महात्मा गांधी की हत्या के तार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने का मामला

आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में राहुल के एक भाषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल गांधी ने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगाया था, जिसके बाद कुंटे ने भिवंडी मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की थी।

2015: संघ कार्यकर्ताओं पर मंदिर में न घुसने देने का आरोप-राहुल ने 2015 में दिल्ली में आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जब वे असम में एक मंदिर के दौरे पर जा रहे थे तो संघ कार्यकर्ताओं ने उन्हें मंदिर में घुसने से रोक दिया। इस मामले में संघ कार्यकर्ता अंजन बोरा ने राहुल पर गुवाहाटी में मानहानि की शिकायत की थी।

2017: गौरी लंकेश हत्या मामले को संघ से जोड़ने का आरोप-पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को भाजपा-आरएसएस की विचारधारा से जोड़ने वाली टिप्पणी के लिए राहुल के खिलाफ 2017 में मुंबई में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पहले सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी भी आरोपी थे। हालांकि, सोनिया को बाद में राहत दे दी गई। वहीं, सीताराम येचुरी का निधन हो गया है।

2018: अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट का आरोप-राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल ने कहा था कि शाह ने अहमदाबाद के जिला कोऑपरेटिव बैंक के साथ मिलकर नोटबंदी के दौरान 745 करोड़ के बंद हो चुके नोटों को गलत तरह से बदल लिया था। मामले में बैंक और उसके

चेयरमैन ने राहुल पर अहमदाबाद की अदालत में केस किया था।

2018: प्रधानमंत्री को बताया कमांडर-इन-थीफ-2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी ने घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री पर हमला बोला था। उन्होंने इस दौरान पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए 'कमांडर-इन-थीफ' टिप्पणी की थी। इस मामले में राहुल के खिलाफ भाजपा से महाराष्ट्र प्रदेश समिति के सदस्य महेश श्रीश्रीमाल ने मुंबई में राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

2018: अमित शाह को हत्या का अभियुक्त कहने का आरोप-राहुल पर आरोप है कि कर्नाटक चुनाव के दौरान बंगलूरु में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा था कि भाजपा जो कि ईमानदारी व स्वच्छता की राजनीति करती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हत्या अभियुक्त है। इसके बाद राहुल के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में केस दर्ज हुआ था।

2019: लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शाह पर टिप्पणी के दो केस-2019 के लोकसभा चुनावों से पहले झारखंड के चाईबासा में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के लिए 'हत्यारा' शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल के खिलाफ चाईबासा में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी मामले में उनके खिलाफ एक एफआईआर रांची में भी दर्ज हुई थी।

2019: शाह के खिलाफ टिप्पणी का एक केस अहमदाबाद में भी-इतना ही नहीं राहुल गांधी पर लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही जबलपुर में एक रैली के दौरान भी शाह को 'हत्या केस का आरोपी' बुलाने का आरोप लगा था। इस मामले में अहमदाबाद के कालूपुर वार्ड के कापोरेंटर कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने मेट्रो कोर्ट नम्बर 16 में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

2019: मोदी उपनाम पर अभद्र टिप्पणी का आरोप (तीन केस)-2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी हैं?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसके अलावा दो और जगहों पर शिकायत हुई। इनमें सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा भी सुनाई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से राहुल को राहत दे दी गई।

2022: सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप (2 केस)

कर्मचारियों की कमी से विकास कार्यों की गति धीमी होने की बात से इंकार जिलापं अध्यक्ष

सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के निर्णय से मुरादाबाद जिला पंचायत बोर्ड भी अछूता नहीं है। यहां पर कर्मचारियों की कमी से विकास की रफ्तार धीमी हो गई है।

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो मुरादाबाद। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के निर्णय से मुरादाबाद जिला पंचायत बोर्ड भी अछूता नहीं है। यहां पर कर्मचारियों की कमी से विकास की रफ्तार धीमी हो गई है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष अपने बोर्ड की सच्चाई को सिरे से भी नकारती हैं। उनके मुताबिक यहां पर कोई कर्मचारी की कमी नहीं है, जबकि करोड़ों रुपये से विकास करने वाले इस बोर्ड में काम के दबाव के चलते जो कर्मचारी हैं, वह बेहद परेशान हैं। वह अपना दुःख-दर्द कहीं किससे, क्योंकि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है।

40 करोड़ के आस-पास रहता है बोर्ड का बजट मुरादाबाद जिला पंचायत बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 38.99 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। यह बजट मुरादाबाद के विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया। इससे पहले, मुरादाबाद

जिला पंचायत बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 37.54 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2022-23 में, जिला पंचायत बोर्ड ने 37.54 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया। मुरादाबाद जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में आय और व्यय का ब्योरा भी प्रस्तुत किया गया था।
कभी होते थे 120 कर्मचारी मुरादाबाद जिला पंचायत से चलने वाले विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए कभी यहां पर 120 कर्मचारी होते थे। धीरे-धीरे कर्मचारी रिटायर होते गए। उनकी जगह नई भर्तियां हुईं नहीं। कुछ पदों को सरकार ने खत्म कर दिया और कुछ पर लंबे अर्से से सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा रखी है। पहले तो बोर्ड को ही भर्ती का पॉवर था, जो अब सरकार की ओर से छीन लिया गया है। इस तरह से भर्ती पहले ऑफलाइन होती थी।
आइए जानते हैं, क्या बोले जिला पंचायत के कर्मचारी



जब नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो पंचायत के दफ्तर पहुंचे तो वहां पर बताया गया। अपर मुख्य अधिकारी कम ही आते हैं। कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां बहुत से पद खाली हैं और नई भर्ती नहीं की जा रही है। बड़े बाबू अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। गिनती के हम पांच लोग हैं। स्टाफ बहुत कम है और काम का दबाव बहुत अधिक है, इस वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला पंचायत का काम कोई छोटा नहीं है। जिला पंचायत के कर्मचारियों की बातों से लगा कि उनसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, जिसके कारण उनमें नाराजगी

क्या बोलें, जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली सिंह मुरादाबाद जिला पंचायत बोर्ड की अध्यक्ष शैफाली सिंह से जब बोर्ड की क्रिया-कलाप के बारे में पूछा गया तो बीजेपी बोर्ड का बचाव करते हुए यहां तक कह डाला कि जिला पंचायत मुरादाबाद बोर्ड में कोई पद रिक्त नहीं है। सभी पद भरे हुए हैं और सभी काम समय से पूरे किये जा रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या यह तो वहां काम करने वाले कर्मचारी और जिला पंचायत अध्यक्ष ही बेहतर जानती हैं। दोनों ओर की बातों से यह साफ जाहिर होता है कि बोर्ड के काम में पारदर्शिता कम झोलझाल ज्यादा है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्य:

विकास योजनाओं का संचालन: जिला पंचायत जिले में विकास योजनाओं का संचालन और कार्यान्वयन करती है, जिसमें कृषि, पशुधन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक वानिकी, और परिवार कल्याण कार्यक्रम

शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था: यह सड़कों का निर्माण और रखरखाव, जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, और स्कूलों का संचालन जैसे कार्यों को देखती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास जिला पंचायत लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, और अन्य ग्रामीण रोजगार योजनाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करती है। स्वास्थ्य और स्वच्छता जिला पंचायत स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी योजनाओं की निगरानी करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में सुधार के लिए काम करती है। सामाजिक कल्याण जिला पंचायत सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे कि वयस्क साक्षरता, बाल कल्याण, और युवा कल्याण कार्यक्रमों को लागू करती है।

जी एस टी विभाग और नगर निगम के भ्रष्टाचार को व्यापारियों ने पहुंचाया सीएम तक

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो मुरादाबाद । मुरादाबाद के व्यापारियों ने ऋद्ध और नगर निगम की उत्पीड़न विरोधी नीति को पहुंचाया उठ डूँ तक

आखिरकार मजबूर होकर मुरादाबाद के व्यापारी सीधा प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास आज पहुंच ही गए। वहां पर उन्होंने

नगर निगम के मुखिया से लेकर जीएसटी महकमे के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ



दिनों से जिस तरह से नगर निगम और जीएसटी महकमा मुरादाबाद के व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है। उससे मुरादाबाद के व्यापारी बहुत खफा हैं। जब उनकी सुनवाई नगर निगम और जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने नहीं की। तब आज आखिर में मजबूर होकर मुरादाबाद के व्यापारी सीधा प्रदेश सरकार के मुखिया व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गए। वहां पर उन्होंने नगर निगम के मुखिया से लेकर और जीएसटी महकमे के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में अक्षरसः बताया। साथ में यह भी बताया कि किस तरह से यह दोनों महकमे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। व्यापारियों ने सुविधा शुल्क लेने का भी इन पर आरोप लगाया।
जीएसटी महकमा वसूल रहा है सुविधा शुल्क उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के विपिन गुप्ता ने

बताया कि मुरादाबाद इकाई से जुड़े व्यापारी जब मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने अपना दुखड़ा सीएम योगी को सुनाया। उन्होंने सीएम को बताया कि मुरादाबाद में जीएसटी की सचल दल इकाइयों द्वारा भौतिक सत्यापन के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही हैं। माल के सारे कागजात उपलब्ध होने पर भी व्यापारियों का उत्पीड़न इसलिए किया जाता है जिससे उन्हें सुविधा शुल्क मिले। जब सचल दल इकाइयों को सुविधा शुल्क मिल जाता है तब सचलदल के अधिकारी माल को छोड़ देते हैं। वरना कागजों में कमी दिखाकर माल को सील कर देते हैं। मुरादाबाद के व्यापारियों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सीएम से यह भी कहा कि जिन व्यापारियों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है और वह लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उन्हें भी शस्त्र लाइसेंस दिया जाए।

भ्रष्ट हैं नगर निगम के अधिकारी

मुरादाबाद के व्यापारियों ने नगर निगम के अधिकारियों को भ्रष्ट बताते हुए भ्रष्टाचार और उनकी ओर से किये जा रहे व्यापारियों के उत्पीड़न के बारे में सीएम को अवगत कराया। व्यापारियों ने नगर निगम के बारे में सीएम को बताया। कि शहर में अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इसमें नगर निगम के अधिकारी सबसे ज्यादा व्यापारियों को परेशान कर हैं। जबकि उन पर अंकुश लगाने का काम मेयर का भी है।

व्यापारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें कहा कि आयुष्मान योजना में सरकार की ओर से जो 70 वर्ष की सीमा रखी गई है उसे घटाकर 60 वर्ष किया जाए।

इन व्यापारियों ने सीएम से मुलाकात की मुख्यमंत्री से मिलने वालों में उद्योग व्यापार संगठन के महानगर महामंत्री सुनील अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन गुप्ता, अधिवक्ता संदीप गुप्ता, आशुतोष गुप्ता आदि व्यापारी शामिल रहे।



यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में जगह-जगह लगाए गए सेफ्टी स्टैंड पर लोगों के बीच सेल्फी लेने का क्रेज देखा जा रहा है पब्लिक सेल्फी लेने के साथ इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए ट्रैफिक रूल्स नहीं तोड़ने की शपथ भी ले रही हैं दो पहिया वाहन चालक हो या फिर कार सवार ज्यादातर लोग सेफ्टी पॉइंट पर सेल्फी क्लिक कर

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर रहे हैं पब्लिक एसपी सतपाल अंतिल की इस अनोखी मुहिम की सराहना कर रही है लोग अपने परिवार के सदस्यों और फ्रेंड्स के साथ इन सेल्फी स्टैंड पर यातायात नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं।

मुरादाबाद के रहने वाले माजिद अली ने एस एस पी सतपाल अंतिल की मूहिम मिशन रोड सेफ्टी की सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है खास तौर पर युवा इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

को फ्लैट पर कब्जा दिया गया, लेकिन बाद में उन फ्लैट को दूसरों को ज्यादा दाम पर बेच दिया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग की तरह है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने उन्नति फॉर्च्यून ग्रुप के अरण्या हाउसिंग प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। पंकज मित्तल पुत्र क्रांति प्रसाद गवर्नमेंट कंट्रिक्टर है। बिजली विभाग और सड़क निर्माण के बड़े ठेकेदार हैं। साथ में ही बिल्डर भी हैं। लखनऊ की उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर से भी यह जुड़े हुए हैं।

मिशन रोड सेफ्टी से जुड़ी महिलाएं व युवा, उत्साहित होकर ले रहे सेल्फी

सक्रिय शिवसैनिक सम्मान समारोह 19 अप्रैल को

मेरठ, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मेरठ इकाई की छोपी टैंक स्थित शिवसेना कार्यालय पर हुई बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख संदीप गर्ग ने की व संचालन महानगर प्रमुख मोहित त्यागी ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव व पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेन्द्र तोमर ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता को ओर तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है, जो शिव सैनिक तन-मन-धन से संगठन

की सेवा में लगे हैं ऐसे सभी शिव सैनिकों का 19 अप्रैल 2025 को दिल्ली रोड स्थित, रोडवेज के सामने चैम्बर आफ कामर्स में सक्रिय शिवसैनिक सम्मान समारोह का आयोजन कर सम्मानित किया जाएगा, सभी शिव सैनिकों को संगठन में सक्रिय करके संगठन को ओर मजबूती देने का काम किया जायेगा। सम्मान समारोह के पश्चात शिवसेना सिनेमा इकाई चित्रपट सेना के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी

उसी स्थान पर होगा। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार, युवा सेना जिलाध्यक्ष अवनीश आर्य व महानगर अध्यक्ष सनी प्रधान, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष सोनिया उत्तम,कमल प्रजापति , जसवीर सिंह, अरु पी सिंह, प्रदीप कुमार, पूजा सिंघल, अमरजीत बाल्मीकि, रवि भगत, बोस सिद्धार्थ, नौशाद डान, इम्तियाज चौधरी, वसीम ठेकेदार, नाजिया आदि शामिल रहे।

प्रदेश के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशान्त कुमार द्वारा व्यवस्थाओं का किया गया निरीक्षण।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो। कानपुर। आगामी वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह एवं डीजीपी उओप्रओ प्रशान्त कुमार द्वारा कानपुर नगर का भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा रूट व्यवस्था, मेट्रो स्टेशन, हैलीपैड, जनसभा स्थल एवं पार्किंग स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए, जिससे कि कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित की जा सकें। निरीक्षण के उपरान्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक



विश्वविद्यालय कानपुर (उओअ) विश्वविद्यालय परिसर में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई। गोष्ठी में एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह, पुलिस आयुक्त अखिल कुमार, मंडलायुक्त कानपुर के विजयेन्द्र पांडियन,आईजी रेंज कानपुर जोगेंद्र

कुमार,जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह,अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) हरीश चंद्र सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा सुरक्षा, यातायात और जनता की सुविधा को लेकर सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

पत्रकारिता दिवस पर कानपुर प्रेस क्लब करेगा बड़ा आयोजन

नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।

कानपुर। दिल्ली और लखनऊ से आएंगे मुख्य अथिति। पत्रकारों का होगा सम्मेलन व गोष्ठी, विधिक राय के लिए वकीलों का बनेगा पैनल।

कानपुर, कानपुर प्रेस क्लब कार्यक्रमों की बैठक में तय किया गया कि आगामी 30 मई को पत्रकारिता दिवस पर कानपुर प्रेस क्लब पत्रकार सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा के साथ समाधान के रास्ते भी तालाश होगी। दिल्ली और लखनऊ से अनुभवी वरिष्ठ पत्रकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। वे



पत्रकारिता के अनुभव साझा करने के साथ मार्गदर्शन भी करेंगे। इस मौके शहर के दस पत्रकारों को जुगुल किशोर शुक्ल पत्रकारिता सम्मान से

नवाजा जाएगा। नाम अखबारों और चैनलों के संपादकीय प्रभारी तय करेंगे। बैठक में यह भी तय हुआ की पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं का पैनल

बनाया जाएगा,जो जरूरत पड़ने पर पत्रकारों की विधिक सलाह देंगे,साथ ही विधि बीट की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को कानूनी जानकारी के साथ सुझाव भी देंगे। कानपुर प्रेस क्लब की महिला विंग और प्रशासनिक कमेटी का भी शीघ्र गठन किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष सरस वाजपेई,महामंत्री शैलेश अवस्थी, वरिष्ठ मंत्री मोहित दुबे,मंत्री शिवराज साहू,कोषाध्यक्ष सुनील साहू,कार्यकारिणी सदस्य मयंक मिश्रा,गगन पाठक,दीपक सिंह, रोहित निगम,उत्सव शुक्ला,अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे।

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैनात होंगे विशिष्ट शोधकर्ता, 30 हजार मिलेगा मानदेय

लखनऊ-उत्तर प्रदेश में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट शोधकर्ता तैनात किए जाएंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड 18 फेलो व एक कार्यक्रम समन्वयक भी चुनेगा। 10 हजार रुपये यात्रा भत्ता भी मिलेगा।

ये सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देंगे। उत्तर प्रदेश में ईको टूरिज्म को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत उत्तर प्रदेश

ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (यूपीईटीडीबी) द्वारा 18 ईको टूरिज्म विशिष्ट शोधकर्ता (फेलो) और एक कार्यक्रम समन्वयक तैनात किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ईको पर्यटन

को बढ़ावा देना है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के सामने हाल ही में इसकी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। शासन की हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। चयनित फेलो को प्रतिमाह

30 हजार रुपये मानदेय और 10 हजार रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इस योजना पर सालाना 91.20 लाख रुपये खर्च होंगे। फेलो एक साल के लिए चुने जाएंगे। इसे आवश्यकता के आधार पर एक

और साल के लिए बढ़ाया जा सकेगा। 18 फेलो की नियुक्ति पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव और वन विभाग के प्रमुख सचिव की आपसी सहमति से तय किया जाएगा।

कार्यक्रम के तहत चयनित फेलो और समन्वयक ईको टूरिज्म से संबंधित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने, स्थानीय समुदायों और हितधारकों को प्रशिक्षण और जागरूक करेंगे। साथ ही ईको

टूरिज्म स्थलों के प्रचार-प्रसार, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ तालमेल बनाने, पर्यटन से संबंधित डेटा को सुव्यवस्थित करने, चल रही परियोजनाओं की निगरानी आदि से जुड़े काम भी करेंगे।

संपादकीय

चोरी व कुप्रबंधन पर अंकुश जरूरी

जिस राज्य में उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही हो, वहां बिजली चोरी का चिंताजनक स्थिति तक पहुंच जाना, निश्चित ही गंभीर मसला है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड को यदि वर्ष 2024-25 में दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है तो उसकी बड़ी वजह पंजाब में बिजली चोरी का बेहद गंभीर स्थिति को पार कर जाना है। ये नुकसान प्रतिदिन के हिसाब से 5.5 करोड़ रुपये बैठता है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह नुकसान सिस्टम की विफलता या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नहीं हुआ है बल्कि जानबूझ कर सुनियोजित तरीके से की जा रही बिजली चोरी की वजह से हुआ है। राज्य में घाटे में चल रहे लगभग 77 फीसदी फीडर सीमावर्ती और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित हैं, जिनमें पट्टी, भिखीविंड, अजनाला और जीरा जैसे डिवीजन शामिल हैं, जिनमें से कई संगठित बिजली चोरी के लिए कुख्यात हैं। भूमिगत कुंडी कनेक्शन से लेकर मीटर से छेड़छाड़ और पिलर बॉक्स को निष्क्रिय करके चोरी करना एक आम तरीका बन गया है। आरोप है कि ये चोरी आमतौर पर राजनीतिक व धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण में होती है। दरअसल, इस विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल है कि जबकि लोगों को पहले ही छह सौ यूनिट तक सब्सिडी वाली यानी कि मुफ्त बिजली का लाभ उठाने का मौका मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बिजली चोरी की प्रवृति कम नहीं हो रही है। दरअसल, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का संकट यहीं खत्म नहीं हो जाता। पीएसपीसीएल कुप्रबंधन व व्यवस्थागत संकटों से भी गंभीर रूप से जुझ रहा है। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड कर्मचारियों की भारी कमी की चुनौतियों से जुझ रहा है। बिजली विभाग में 4900 से अधिक लाइनमैनों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन फिजहाल केवल 1313 लाइनमैन काम कर रहे हैं। अकेले लुधियाना में ही जूनियर इंजीनियर के आधे पद खाली हैं। बिजली चोरी रोकने तथा बेहतर व्यवस्था के लिये कर्मचारी भर्ती अभियान को गति दी जानी चाहिए।

दरअसल, पीएसपीसीएल में पर्याप्त कर्मचारी न होने के कारण विभागीय कार्यक्षमता बुरी तरह से प्रभावित है। जब भी किसी इलाके में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होता है तो तत्काल कार्रवाई बिजली बहाल करने के लिये नहीं हो पाती। फलतः लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों की नाराजगी लगातार बढ़ती है। विभाग में पक्के मुलाजिमों की नियुक्ति न होने पर कम वेतन पाने वाले सॉिदा कर्मचारियों के जरिये व्यवस्था बनाने की कोशिश होती है। जिसके चलते संविदा कर्मचारियों द्वारा अकसर आंदोलन किया जाता है। वे खुद को पक्का करने की मांग करते रहते हैं। उनका आरोप होता है कि कम वेतन देकर उनसे ज्यादा काम कराया जाता है। जानकार मानते हैं कि सिर्फ संविदा कर्मचारियों पर अत्याधिक निर्भरता केवल तदर्थवाद को ही बढ़ाएगी। हालांकि, नियामक आयोग ने इस गड़बड़ी को भी चिन्हित किया है। लेकिन इससे ही समस्या का समाधान संभव नहीं है, संकट के निराकरण को गंभीर प्रयासों की जरूरत महसूस की जा रही है। इस समस्या का व्यापक स्तर पर समाधान तभी संभव है जब राज्य के नेतृत्व द्वारा इच्छा-शक्ति को दर्शाया जाए।। समय की मांग है कि भारी घाटे वाले फीडरों में वित्तीय प्रबंधन के लिये लक्षित कार्रवाई की जाए। साथ ही लोगों को ईमानदारी से बिजली के उपयोग के लिये प्रोत्साहित किया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि छेड़छाड़ न किये जा सकने वाले स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। इस दिशा में उठाए गए कदम समस्या का वास्तविक निस्तारण करने वाले होने चाहिए। साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिये सख्त दंड का भी प्रावधान किया जाना जरूरी है। बिजली चोरी में लिप्त लोगों की पहचान होने पर उन्हें दंडित किया जाना जरूरी है। साथ ही ऐसे लोगों को मुफ्त बिजली पाने की योजना का लाभ उठाने के अधिकार से भी वंचित किया जाना चाहिए। दरअसल, सख्त व पारदर्शी दंड व्यवस्था ही चोरी की प्रवृति पर अंकुश लगा सकती है। पीएसपीसीएल को अधिक नुकसान नहीं उठाना चाहिए, जबकि पंजाब पहले ही कर्ज का बोझ उठाने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर है।

शिक्षा या शोषण? निजी स्कूलों की मनमानी पर कब लगेगी लगाम

सुरेंद्र मलानिया
देश में शिक्षा का स्तर भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी और मुनाफाखोरी ने इस पवित्र कार्य को एक व्यवसाय में तब्दील कर दिया है। पब्लिक स्कूलों के नाम पर अब बच्चों की पढ़ाई नहीं, अभिभावकों की जेब काटी जा रही है। किताबों, यूनिफॉर्म, जूतों और अन्य सामानों पर स्कूल संचालकों द्वारा मोटा कमीशन लिया जा रहा है। इस स्थिति में मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए बच्चों को पढ़ाना एक बड़ी चुनौती बन गया है।
बढ़ती लूट: कमीशन की चक्की में पिसते अभिभावक
आज अधिकांश निजी स्कूल कुछ विशेष प्रकाशकों की किताबें लागू करते हैं और यूनिफॉर्म व जूते तय दुकानों से खरीदने का दबाव बनाते हैं। स्कूलों का इन दुकानों से सीधा गठजोड़ होता है, जहाँ से उन्हें मोटा कमीशन मिलता है। नतीजा यह होता है कि जो किताबें

भारत में ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध है।

भारत में 43 यूनेस्को आधारित विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 35 सांस्कृतिक हैं, सात प्राकृतिक हैं और

कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित स्थल है। 62 अन्य संभावित सूची में हैं, यहाँ ऐतिहासिक स्थलों का

खजाना है जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। 2024 में, असम से चराइदेव मोइदम

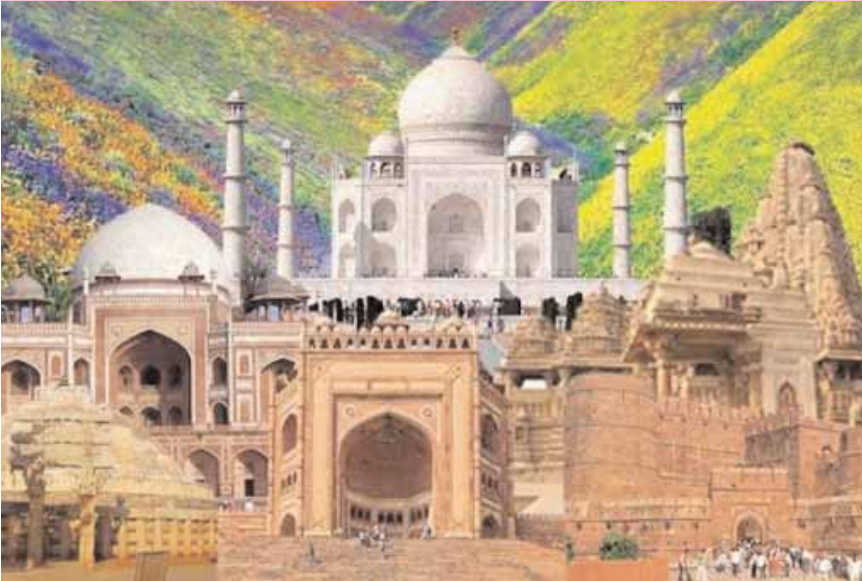
विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली नवीनतम भारतीय प्रविष्टि बन गई। अहोम राजघरानों के दफन टीलों में गुंबददार कक्ष हैं, जो अक्सर दो-मंजिला होते हैं और जहां मेहराबदार मार्गों से पहुँचा जा सकता है। इन कक्षों में, मृतक को उनके सामान, जिसमें कपड़े और आभूषण, हथियार, फर्नीचर और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के साथ सुरक्षित रखा गया है।

विश्व विरासत दिवस सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पलों को लाने में ही मदद नहीं करता बल्कि यह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम भी है

विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस मानव सभ्यता के इतिहास और विरासत को एक साथ सम्मान देने एवं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षित करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक परिदृश्यों और संरचनाओं का जश्न मनाना और उन पर ध्यान आकर्षित करना है, जो व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई जो विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। यह संधि सन्-1972 में लागू की गई। प्रारंभ में मुख्यतः तीन श्रेणियों में धरोहर स्थलों को शामिल किया गया। पहले वह धरोहर स्थल जो प्राकृतिक रूप से संबद्ध हो अर्थात प्राकृतिक धरोहर स्थल, दूसरे सांस्कृतिक धरोहर स्थल और तीसरे मिश्रित धरोहर स्थल। वर्ष 1982 में इकोमार्क नामक संस्था के ट्यूनिशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस में यह बात उठी कि विश्व भर में विरासत दिवस का आयोजन किया जाना चाहिए। यूनेस्को के महासम्मेलन में इसके अनुमोदन के पश्चात विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की गई। हर साल धरोहर दिवस की एक खास थीम होती है। साल 2024 में विश्व विरासत दिवस की थीम विविधता की खोज और अनुभव थी। वहीं इस साल थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत: आईसीओएमएस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख। यह थीम गौरवशाली अतीत में विश्व संस्कृतियों की सुंदरता को बढ़ाने एवं संरक्षित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

दुनिया के तमाम देशों में कई सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरें हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित किया है। इनमें से आठ ऐसी विश्व धरोहर हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। जिनमें मिस्र में मौजूद गीजा का ह्यूप्ट पिरामिडह्क आज भी रहस्य बना हुआ है।481 फीट ऊंचा

विश्व विरासत दिवस- 18 अप्रैल, 2025



यह पिरामिड विश्व के आठ प्राचीन अजूबों में शामिल है और माना जाता है कि इसे चांद से भी देखा जा सकता है। माचू पिच्चू, पेरू यह ऐतिहासिक स्थल पेरू की पहाड़ियों पर बसा है और रहस्यमयी और खूबसूरत माचू पिच्चू को ह्राइकाओं का खोया हुआ शहरह्क भी कहा जाता है। चीन की महान दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई करीब 21,196 किलोमीटर है। यह दीवार कई राजाओं और साम्राज्यों द्वारा रक्षा के लिए बनाई गई थी। आगरा का ताजमहल मोहब्बत एवं प्रेम की सबसे खूबसूरत मिसाल है। इसे शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर की इमारत भारत की सबसे मशहूर धरोहरों में से एक है। क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील रियो डी जेनेरियो में स्थित यीशु की यह विशाल प्रतिमा 30 मीटर ऊंची है। यह प्रतिमा न सिर्फ धार्मिक प्रतीक है, बल्कि शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। पेट्रा, जॉर्डन रेगिस्तान के बीच स्थित पेट्रा शहर अपनी अनोखी लाल पत्थर की इमारतों और मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसकी वास्तुकला और नक्काशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कोलोसियम, रोम (इटली) प्राचीन रोम के सम्राटों द्वारा बनवाया गया यह विशाल अखाड़ा कभी र्लैडिएटरों की लड़ाई का गवाह था। यह आज भी रोम की पहचान बना हुआ है और विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चिचेन इट्जा, मेक्सिको

का प्रमुख धार्मिक स्थल रहा है। यहां बना ह्याएल कैस्टिलोह्क पिरामिड देखने लायक है। चिचेन इट्जा को मेक्सिको का सबसे संरक्षित पुरातात्विक स्थल माना जाता है। भारत में ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध है। भारत में 43 यूनेस्को आधारित विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें से 35 सांस्कृतिक हैं, सात प्राकृतिक हैं और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक मिश्रित स्थल है। 62 अन्य संभावित सूची में हैं, यहाँ ऐतिहासिक स्थलों का खजाना है जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। 2024 में, असम से चराइदेव मोइदम विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली नवीनतम भारतीय प्रविष्टि बन गई। अहोम राजघरानों के दफन टीलों में गुंबददार कक्ष हैं, जो अक्सर दो-मंजिला होते हैं और जहां मेहराबदार मार्गों से पहुँचा जा सकता है। इन कक्षों में, मृतक को उनके सामान, जिसमें कपड़े और आभूषण, हथियार, फर्नीचर और दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं के साथ सुरक्षित रखा गया है।

विश्व विरासत दिवस सिर्फ हमारे जीवन में खुशियों के पलों को लाने में ही मदद नहीं करता बल्कि यह देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम भी है। यह पर्यटन को प्रोत्साहन देने का सशक्त माध्यम है। भारत की अर्थव्यवस्था पर्यटन-उद्योग के इर्द-गिर्द घूमती रही है। भारत की प्रमुख आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय शक्तियों में से एक है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद भारत को न केवल अपने सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को पुनर्स्थापित करना था, बल्कि उसे एक ऐसे लोकतांत्रिक देश का निर्माण करना था जो अपने नागरिकों को समान अवसर और अधिकार प्रदान कर सके। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम ह्रस्वर्णिम भारत-विकास के साथ विरासतह्क है। यह थीम देश की विरासत को संभालते हुए भारत की प्रगति की यात्रा को दर्शाती है। भारत अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।

राजस्थान भारत का एक राज्य है जो विश्व विरासत का समृद्ध केन्द्र है, यह पर्यटन के लिए सबसे समृद्ध

अमरोहा के हसनपुर में सपा नेता ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप संविधान को खत्म करना चाहती है रोजगार की बजाय खेलों में उलझाती है



अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी एससी एसटी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती स्वाभिमान स्वामान समारोह में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांठ विधायक कमाल अख्तर ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय वर्ल्ड कप चैंपियन एशिया कप और फुटबॉल टूनामेंट जैसे आयोजनों में उलझाए रखना चाहती हैं संविधान के अनुसार - कमाल अख्तर ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में सभी को बराबरी का अधिकार दिया है लेकिन भाजपा न सिर्फ संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है बल्कि उसे खत्म करना चाहती है उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है साथी कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान के मार्ग पर चलकर देश की सेवा कर रही है उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए कभी औरंगजेब तो कभी हुमायूं का मुद्दा उठाती है कार्यक्रम के अध्यक्षता मास्टर मंगली सिंह ने की और संचालन नवल जाटव ने किया इस अवसर पर प्रदेश सचिव आरिफ अख्तर चंद्रपाल सिंह सैनी अखिलेश जाटव बदर कुरेशी समेत कई नेता मौजूद रहे।

भाईचारा मिलन समारोह का किया आयोजन: डॉ० आर के मैसी



ेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो। नई दिल्ली। प्रेम धाम ऑडिटोरियम दिचाऊं रोड नजफगढ़ में भाईचारा मिलन समारोह का आयोजन डॉ आर.के. मैसी संस्थापक ह्यूमन केयर इंटरनेशनल द्वारा किया गया जिसमें मुख्य अतिथि प्रो॰ आनंद कुमार वरिष्ठ समाज शास्त्री थे, विशिष्ट अतिथियों में प्रो॰ राम अवतार शर्मा दृष्टिहीन, श्रीमती रमा भल्ला राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित, शिक्षाविद धर्म बीर सिंह, शिक्षाविद श्री जे सी अरोरा, अशोक सहरावत, राजीव यादव समाजसेवी, विवेक त्यागी अध्यक्ष भारत विकास संगम दिल्ली, वरुण कथुरिया सम्पादक एवन न्यूज चैनल, राजेश शर्मा अध्यक्ष प्रकृति भक्त फाउंडेशन, अख्तर खान फिल्म मेकर, अश्वनी शर्मा प्रकृति भक्त, डॉ॰ राम निवास यादव, डॉ॰ फारुकी, नीतू

राज्य माना जाता है। राजस्थान की पुरातात्विक विरासत या सांस्कृतिक धरोहर केवल दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थल के लिए नहीं है बल्कि यह राजस्व प्राप्त का भी स्रोत है। यूं तो भारत के सभी राज्यों में समृद्ध विरासत देखने को मिलती है। पर्यटन क्षेत्रों से कई लोगों की रोजी-रोटी भी जुड़ी है। प्राकृतिक सुंदरता और महान इतिहास से संपन्न राजस्थान में पर्यटन उद्योग समृद्धिशाली है। राजस्थान देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, दोनों के लिए एक सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन स्थल है। भारत की सैर करने वाला हर तीसरा विदेशी सैलानी राजस्थान देखने जरूर आता है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलों और जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर के भव्य दुर्ग भारतीय और विदेशी सैलानियों के लिए सबसे पर्यदीवा जगहों में से एक हैं। इन प्रसिद्ध विरासत स्थलों को देखने के लिए यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं। जयपुर का हवामहल, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के धोरे काफी प्रसिद्ध हैं। जोधपुर का मेहरागढ़ दुर्ग, सवाई माधोपुर का रणथम्भोर दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी प्रसिद्ध है। यहाँ शेखावटी की कई पुरानी हवेलियाँ भी हैं जो वर्तमान में हैरीटेज होटलें बन चुकी हैं।

विश्व विरासत दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि चिंतन, कार्रवाई और प्रतिबद्धता का दिन है। इस अक्सर का उपयोग सभी के लाभ के लिए अपने सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संरक्षण में योगदान देना है। यह वैश्विक आयोजन सांस्कृतिक धरोहर के प्रति चिंतन करता है और इन अमूल्य खजानों के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन सांस्कृतिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के महत्व को पहचानने, दुनिया भर में उनकी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व के लिए सराहना को बढ़ावा देने का अवसर है।

सैफनी नगर में विकास की नई इबारत

वार्ड 6 समेत कई क्षेत्रों में बदली तस्वीर

आने वाले दिनों में सैफनी एक विकसित और आदर्श नगर के रूप में पहचान बनाएगा।

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

उत्तर प्रदेश रामपुर सैफनी को नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद यहाँ विकास की रफ्तार ने नई ऊंचाइयों को छू लिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष फैजान खान के कुशल नेतृत्व में नगर में विभिन्न विकास योजनाएं तेजी से आकार ले रही हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर नागरिक सुविधाओं तक, हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से वार्ड नंबर 6 में भी बदलाव की बहार बह रही है, जहाँ सभासद मोहम्मद रफी उर्फ गुड्डू के प्रयास काबिले-तारीफ हैं। वे वार्ड के लोगों की समस्याओं पर निगरानी रखते हैं और उनके त्वरित समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। वार्ड 6 में अधिकांश नई रिहाइश हैं। नए मकान बने हैं। जिस कारण वहां मार्ग भी नए विकसित हुए हैं। पहले अधिकतर मार्गों पर पानी भरा रहता था। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुआ करती थी। चेयरमैन के प्रयासों से अब इस वार्ड



सभासद मो. रफी उर्फ गुड्डू भार्ही

के अधिकांश मार्गों पर सीसी डलवा दिया गया है। बचे हुए मार्गों का निर्माण कार्य कराने के लिए भी भरपूर कोशिश की जा रही है। वार्ड के विकास में सभासद का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान का कार्य तेजी से जारी है, और सभासद व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच जाकर इस प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटे हैं।



चेयरमैन फैजान खान

2.5 करोड़ की लागत से मैरिज हॉल का निर्माण जाटवान मोहल्ले में बन रहा भव्य मैरिज हॉल अब अपने अंतिम चरण में है। इस परियोजना के पूर्ण होने से स्थानीय लोगों को विवाह जैसे आयोजनों के लिए बाहर महंगे हॉल किराए पर नहीं लेने पड़ेंगे। बस स्टैंड पर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सुंदर लाइटिंग, रंगाई-पुताई और बैठने की सुविधाओं से

यह स्थल आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। धार्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए रामगंगा किनारे आधुनिक शमशान घाट का निर्माण हो रहा है, जिससे अंतिम संस्कार की समुचित सुविधा नगरवासियों को मिल सके। युवाओं के लिए जिम और पार्कस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए एक मॉडर्न जिम और नागरिकों के लिए टहलने एवं बच्चों के खेलने हेतु पार्क का निर्माण किया जा रहा है। शिक्षा के लिए आधुनिक लाइब्रेरी बनाई जा रही है। नगर की गलियों और मुख्य मार्गों पर एलईडी लाइटिंग लगाई जा रही है, जिससे न सिर्फ रात में रास्ते रोशन रहते हैं, बल्कि सुरक्षा भी बेहतर हुई है।

रमैरा उद्देश्य है कि सैफनी का हर कोना विकास से अछूता न रहे। हम शासन-प्रशासन से सतत संपर्क में हैं और हर योजना को जमीनी हकीकत बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष फैजान खान

नंगे पांव और फटे कुर्ते का असर, बदल गए हैं पुलिस कमिश्नर

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नन्द किशोर गुर्जर के नंगे पांव और फटे कुर्ते का असर यह रहा कि सरकार ने पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का तबादला कर हुए उन्हें आईजी रेंज प्रयागराज बनाया है। कमिश्नर अजय मिश्रा का ट्रांसफर होने के बाद बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के सेंकड़ों समर्थक ढोल बजाते हुए घर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर के ट्रांसफर के बाद अब समर्थकों ८ समाज के लोगों ने अपने विधायक से फटा कुर्ता उतरने की गुजारिश कर उन्हें नया कुर्ता और पगड़ी भेंट की है। बता दें 20 मार्च को विधायक रामकथा कलश यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के साथ हुई नोकझोंक के दौरान विधायक का कुर्ता फटा था। उसी दिन से विधायक नंदकिशोर गुर्जर



फटे कुर्ते में थे। दरअसल पुलिस कमिश्नर से विवाद के बाद बीजेपी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी मिला था। प्रदेश अध्यक्ष से की थी पुलिस कमिश्नर को मुलाकात के दौरान लोनी विधायक ने पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाये थे। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार के दौर से ही वे कलश यात्रा निकाल रहे हैं। बीते वर्ष में भी यात्रा निकली थी। क्या कलश यात्रा निकालना अपराध है। पुलिस कमिश्नर के इशारे पर

जानबूझकर यात्रा रोकी गई। इस दौरान उनके और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई। अब पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर चर्चा में गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर और भाजपा विधायक के बीच हुई तनातनी का मामला भी ट्रांसफर को लेकर राजनीतिक गलियारों में कौतूहल का विषय बना हुआ है बता दें कि अजय कुमार मिश्रा की जगह जे रविंद्र गौड़ को गाजियाबाद का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

कुँ. आर. सी. महिला महाविद्यालय में ऑपरेशन जागृति फेस- 4 का शुभारंभ किया गया।

मैनपुरी। कुँ. आर. सी. महिला महाविद्यालय, मैनपुरी में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार और अपराध में कमी लाने के उद्देश्य से संचालित कार्यक्रम ऑपरेशन जागृति फेस- 4 का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचायों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं उनके सम्मुख दीप प्रज्वलन के पश्चात किया गया। महाविद्यालय की संयुक्त सचिव डॉ सुशीला त्वागी ने कार्यक्रम का आगाज करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बच्चियों और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है ऐसे में मिशन जागृति उन्हें नई दिशा प्रदान कर पथ प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है। महाविद्यालय की प्राचायों डॉक्टर शेफाली यादव ने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं में स्व सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करते हुए ही हम एक सशक्त समाज और राष्ट्र की नींव रख सकेंगे। ऐसे में यह कार्यक्रम अपनी महनीय भूमिका निभाएगा। तत्पश्चात एन.सी.सी. कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सविता ने सभी छात्राओं को आपात स्थिति में स्व सुरक्षा हेतु सेल्फ डिफेंस संबंधी मूक्स का प्रशिक्षण दिया। छात्राओं में खुशी ओझा, सृष्टि सिंह, नेहा इत्यादि ने इस कार्यक्रम में विशेष रुचि एवं उत्साह के साथ हिस्सा लिया। गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं ने शानदार रंगोली बनाई।

उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालय की शिक्षिका डॉ. मधु गुप्ता, डॉ. कीर्ति जैन, डॉ.अनीता सिंह, डॉ.कुसुम यादव, डॉ. विभा जैन तथा अन्य शिक्षक - शिक्षिकाओं के साथ समस्त छात्राएं एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ भी मौजूद रहे।

पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवारों को साध्वी ऋतंभरा ने दिलाई नई जिंदगी

मथुरा। वृंदावन में वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी ऋतंभरा ने समाजसेवा का एक और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिल्ली के वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज के पास पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू परिवारों को एक नया जीवन प्रदान किया है। परम शक्तिपीठ के माध्यम से 25 पक्के घर बनवाकर इन परिवारों को सौंप गए, जिनमें बिजली, पानी और शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन आवासों के साथ ही साध्वी ऋतंभरा द्वारा मां सर्वमंगला मंदिर, सत्संग हॉल, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र तथा पुरुषों के लिए स्वरोजगार के लिए 10 रेहड़ी-रिक्शे भी प्रदान किए गए। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5000 लीटर के तीन टैंक और तीन सबमर्सिबल



पंप लगाए गए हैं। यह सभी पहल तब शुरू हुई जब साध्वी ऋतंभरा ने पाकिस्तान से विस्थापित इन हिंदू परिवारों की दुर्दशा देखी जो सिग्नेचर ब्रिज के नीचे झुगियां में रह रहे थे। जंगलों में असुरक्षित परिस्थितियों में रह रहे इन परिवारों के पास न तो पीने का पानी था और न ही कोई सुरक्षा। उनके रहन-सहन को देखकर वह व्यथित हुई और उन्होंने तुरंत इनके पुनर्वास का बीड़ा उठाया। घर की चाबियां परिवारों को सौंपते हुए दीदी

मां ने कहा आपने पाकिस्तान में अत्याचार सहते हुए भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा यह बहुत बड़ा बलिदान है। इस पुनर्वास कार्यक्रम में परम शक्तिपीठ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सीबी पाटोदिया, उपाध्यक्ष जय भगवान अग्रवाल, सचिव संजय भैया, अशोक सारनी, साध्वी शिरोमणि, स्वस्तिका, दीपक खत्री, बीआर सिंगला आदि लोग मौजूद थे। संचालन डॉ. उमाशंकर राही ने किया।

सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लिपिक को पीटने का मामला लखनऊ तक गुंजा

मथुरा। सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने लिपिक के साथ की मारपीट के बाद बुधवार को पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने तीन घंटे तक कामकाज ठप रखा और कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। भनक लगने पर सिटी मजिस्ट्रेट दौड़े-दौड़े पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे। बंद कमरे में उन्होंने लिपिक से माफी मांगी। हालांकि उन्होंने इसे बेतुका बताया। वहीं यूनियन के कर्मचारियों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। दरअसल, मंगलवार डेढ़ बजे पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष व पीडब्ल्यूडी के प्रधान सहायक गोपाल प्रसाद की



एनआईसी गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों से बाइक कलेक्ट्रेट परिसर में ले जाने पर नोकझोंक हो गई थी। आरोप है कि सुरक्षाकर्मी की शिकायत के बाद सिटी मजिस्ट्रेट व उनके सुरक्षाकर्मियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस बात से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व कर्मचारी आक्रोशित हैं। वहीं

सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि गोपाल प्रसाद यहीं कार्यरत हैं। वह लिपिक को ठेकेदार समझ रहे थे। हालांकि घटना के दौरान पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे थे कि गोपाल यहीं काम करता है। बावजूद इसके सिटी मजिस्ट्रेट लिपिक को पीटते रहे।

वृंदावन के लिए करोड़ों की परियोजनाओं के बाद भी गंदगी का साम्राज्य



मथुरा। वृंदावन में धर्मनगरी को चमकाने के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक करोड़ों रुपये की परियोजनाएं शुरू की हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। नगर निगम की लापरवाही और ठेकेदार कंपनियों की मनमानी के कारण पवित्र नगरी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। गलियों में कूड़े के ढेर, नालियों का ओवरफ्लो और सड़कों पर बहता गंदा पानी अब आम नजारा बन चुका है। हाल ही में वार्ड नंबर 70 की सफाई व्यवस्था का ठेका बीवीजी कंपनी को दिया गया है लेकिन बिहारी जी मंदिर के आसपास की स्थिति बेहद खराब है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सफाई का कार्य भीड़ के समय किया जाता है सुबह नहीं, बल्कि दोपहर 11 बजे झाड़ू लगती है और कूड़ा उठाने का समय होता है शाम 6:30 बजे। जब बाजार सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला होता है। जबकि मंदिर दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक बंद रहता है और उस समय बाजार भी शांत रहता है। बावजूद इसके सफाई नहीं की जाती। गुरुकुल से राजपुर जाने वाले मार्ग पर हमेशा गंदा पानी जमा रहता है और इससे गुजरने वाले भक्तों को भारी असुविधा होती है। सबसे पीड़ादायक स्थिति श्री कात्यायनी देवी मंदिर मार्ग पर है जहां श्रद्धालुओं को सीवर के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। जो भक्त नहा-धोकर शुद्ध होकर दर्शन को आते हैं वे इस गंदगी से होकर अपवित्र मन से मंदिर पहुंचते हैं।

निगम की बोर्ड बैठक: हंगामे के बीच एक हजार करोड़ का बजट पास

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

मथुरा। वित्तीय वर्ष 2025-26 की नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। पार्श्वों के आपत्तियों के बीच जयश्री राम के उद्घोष के साथ सभी 15 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। इसमें एक देश एक चुनाव का अनुपूरक प्रस्ताव भी शामिल है। हंगामे के बीच ही सदन में एक हजार करोड़ रुपये के बजट पर जैसे-तैसे मुहर लगी। राष्ट्रगान के बाद बजट सत्र की समाप्ति की घोषणा कर अफसर और मेयर सदन से निकल गए। इस दौरान दो थानों की पुलिस और एक प्लाटून पीएसी मौजूद रही।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के



बजट को लेकर नए साल में पहली बार बुधवार को नगर निगम की बोर्ड बैठक जनरलगंज स्थित कार्यालय पर सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इसमें मथुरा खादर में एमपीएस, वृंदावन में कल्याण मंडप, गेस्टहाउस तथा डिजिटल पुस्तकालय के लिए भूमि दिए जाने, नावों के पंजीकरण एवं लाइसेंस फीस में वृद्धि के लिए बनाई उपविधि का गजट प्रकाशित कराने,

टैक्स में छूट दिए जाने की स्वीकृति, रिफाइनरी क्षेत्र में सफाई कार्य, 17 वाहनों की नीलामी, 25 बोलeros व दो इनोवा क्रिस्टा किराए पर लिए वाहनों का भुगतान, वृंदावन में सफाई कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति, सफाई कार्य के लिए भुगतान की वित्तीय स्वीकृति, जलकल विभाग के 27 कार्य निविदा न होने तक पूर्व की फर्म से कराने समेत कई प्रस्ताव पर

मुहर लगाई गई। हालांकि पार्श्वों के विरोध के बाद वृंदावन में बनने वाले गेस्टहाउस का प्रस्ताव अटक गया है। सदन में पार्श्व नीलम गोयल ने सभी पार्श्वों को एक-एक लैपटॉप व प्रिंटर देने का मुद्दा उठाया। नगर निगम की कब्जाई गई जमीनों को मुक्त कराने का भी मुद्दा गुंजा। वहीं बंदरों का आतंक, वाडों में जलभराव की समस्या समेत कई मुद्दे सदन में गुंजे। इसपर नगरायुक्त ने बंदरों के उत्पात से निपटने के लिए निमाणांधीन एबीसी सेंटर का जल्दी पूरा कराने की बता कही। इस दौरान एमएलसी टा. ओम प्रकाश, उपसभापति मुकेश सारस्वत, महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त शशांक चौधरी समेत अन्य

पुलिस अधीक्षक, ललितपुर द्वारा कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर का किया गया वार्षिक निरीक्षण

कोतवाली ललितपुर परिसर में नव - निर्मित उउळठर कक्ष /विवेचना कक्ष का विधि -विधान से फीता काटकर किया गया उद्घाटन

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर ललितपुर पुलिस अधीक्षक, ललितपुर मो0 मुश्ताक द्वारा कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा सर्वप्रथम गार्द द्वारा सलामी ली गयी । सलामी गार्द का निरीक्षण कर, गार्द में लगे पुलिस अधिकारी/कर्म0गण का टर्न ऑउट को चेक किया गया । तत्पश्चात सम्पूर्ण परिसर का भ्रमण करते हुए कार्यालय, हवालात, कम्प्यूटर कक्ष, महिला हेल्पडेस्क, सीसीटीवी कैमरे, ई-मालखाना, आदि का भौतिक निरीक्षण किया गया तथा सम्पूर्ण परिसर में साफ-सफाई एवं पर्याप्त रोशनी रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

कोतवाली कार्यालय के रजिस्टरों- रजिस्टर नं0 8, एनसीआर रजिस्टर, रजिस्टर नं0 4, ल्यूहार रजिस्टर, क्रियाशील अपराधी रजिस्टर, टॉप-10 रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर , भूमाफिया रजिस्टर, महिला उत्पीडन रजिस्टर आदि को चेक किया गया जिनका रखरखाव संतोष जनक व अध्यावधिक पाया गया ।

फ्लाई शीट व ल॰र. रजिस्टर को चेक कर प्रभारी निरीक्षक , कोतवाली ललितपुर को निर्देशित किया गया कि एच०एस० की चेकिंग साप्ताहिक रूप से करके उसका विवरण जी0डी0 व संबंधित रजिस्टर में अंकित करें ताकि अपराध में प्रभावी नियंत्रण बनाया जा सके और अपसामाजिक तत्वों के विरुद्ध समय-समय पर चेकिंग के पश्चात आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

आई0जी0आर 0एस0 रजिस्टर को चेक कर प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि आइ०जी०आर०एस० शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित,



उचित व गुणवत्तापरक निस्तारण कराना है । आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को गम्भीरता से लेकर लम्बित समस्त प्रकरणों का त्वरित, उचित व गुणवत्तापरक निस्तारण कराकर शत-प्रतिशत फीड बैक लेना सुनिश्चित करें ।

महिला हेल्प डेस्क को चेक किया गया एवं आगन्तुक रजिस्टर को चेक कर थाने पर आने वाली महिला फरियादियों की प्रभावी व उचित सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया तथा पूर्व वर्ष की कृत कार्यवाहियों को भी चेक किया गया ।

तत्पश्चात बन्दी गृह का निरीक्षण किया गया तथा साफ-सफाई रखने हेतु प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया । इसके बाद थाना शस्त्रागार में रखे सभी शस्त्रों को चेक किया गया । साथ ही थाने पर उपस्थित उ0नि0/मु0आ0/आरक्षियों से शस्त्रों की हैण्डलिंग करायी गयी तथा शस्त्रों की नियमित साफ सफाई करने हेतु निर्देशित किया गया तथा संबंधित को नियमित रूप से शस्त्र हैण्डलिंग का अभ्यास कर्मचारियों को कराने हेतु निर्देशित किया गया ।

तत्पश्चात कम्प्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया तथा कोतवाली पर चलने वाली कम्प्यूटरीकृत जीडी को चेक किया गया तो जीडी अद्यतन पायी गयी । सभी सम्बन्धित को अपने कार्यों को पूर्ण रुचि के साथ करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

कोतवाली ललितपुर पर

कार्य सरकार/सूचनाओं का आदान - प्रदान ई-ऑफिस के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया ।

कोतवाली ललितपुर के लम्बित मुकदमों से संबंधित मालों के विधिक निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया कि वह जल्द से जल्द मालों का नियमानुसार विधिक निस्तारण कराये । कोतवाली ललितपुर में लम्बित विवेचनाओं का गुण- दोष के आधार पर विधिक/समयबद्ध निस्तारण करने व मुकदमा से सम्बंधित साक्ष्य को ई-साक्ष्य ऐप पर नियमानुसार समय से अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया ।

माननीय न्यायालय से जारी किए गए सम्मन/वारंट का शत प्रतिशत तामीला कराने हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया ।थाना स्थानीय पर गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल शत प्रतिशत नियमानुसार बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया ।

क्षेत्र के वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब/मादक पदार्थों/पशु तस्करी आदि पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललितपुर को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन थाने पर आने वाले फरियादियों की शतप्रतिशत जन सुनवाई कर उनकी समस्याओं का विधिक निस्तारण किया जाये तथा लोगों से विनम्र व मधुर व्यवहार रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ललितपुर को निर्देशित किया गया कि

पोषण पखवाड़े के तहत किया महिलाओं को जागरूक



नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

चित्रकूट ब्यूरो: दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र मझगांव में आठ से 17 अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे पोषण पखवाड़े के तहत गुरुवार को बरूआ, पिंडरा, केलहैरा आदि पंचायतों की महिलाओं को जागरूक किया गया।

इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण वैज्ञानिक डॉ हेमराज द्विवेदी ने बताया कि पोषण पखवाड़ा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य गर्भवती

महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और छह साल से कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर में सुधार करना है। जिसके तहत अभियान चलाकर समुदाय में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाते हुए और स्वस्थ आहार एवं जीवनशैली को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के द्वारा अपनी तथा अपने परिवार की संतुलित थाली बनाने के बारे में बताया

जाता है।

कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रसार वैज्ञानिक डॉ पंकज शर्मा ने महिलाओं को पोषण वाटिका मे परंपरागत खाद एवं प्राकृतिक कीट नियंत्रक के बारे मे जानकारी दी। मृदा वैज्ञानिक डॉ अशोक शर्मा ने संतुलित उर्वरकों के प्रयोग एवं मृदा नमूना लेने का प्रयोग कराया। साथ ही वर्षा जल संचयन के बारे मे विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर समाज शिल्पी दयाराम यादव सहित 40 महिलायें मौजूद रहीं।

सांसद का रिश्तेदार बताकर महिलाओं से नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों हड़पे

एनपीटी ब्यूरो ललितपुर ललितपुर। झांसी-ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद को अपना रिश्तेदार बताते हुये सिलाई मशीनें दिलाने और नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं से लाखों रुपये लेकर हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। महिला की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है, जबकि इस प्रकरण में सांसद कार्यालय से स्पष्टीकरण भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है।

मुख्यालय के समीपवर्ती ग्राम रजवारा निवासी दीपति राजे पत्नी यशवंत सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह स्वयं सहायता समूह की सचिव है। इस समूह में मानसिंह कुशवाहा, सुहानी राय, सीमा

कुशवाहा, पूजा कुशवाहा आदि सदस्य कार्य करते हैं। बताया कि विगत 6-7 माह पहले नाराहट कस्बा निवासी पवन शर्मा पुत्र अशोक शर्मा उनके गांव पहुंचा और स्वयं को बड़ा पावरफुल बताते हुये कहा कि वह उसे व अन्य महिलाओं को सिलाई मशीन दिलावेगा, जिसके एवज में एक हजार रुपये प्रति महिला की मांग की। इसके अलावा एक विज्ञप्ति भी वह भर्ती कराते हुये ज्वार्डिन लैटर दिलावेगा, जिसके बदले में रुपयों की मांग की गयी और नौकरी न लगने पर रुपये वापस करने की बात कही। बताया कि पवन शर्मा ने गुडासे व समूह की अन्य महिलाओं से

मशीन दिलाने के नाम पर 12 हजार रुपये व नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख 25 हजार कुल 3 लाख 37 हजार रुपये ले लिये। किन्तु अभी तक न तो महिलाओं को सिलाई मशीन दिलायी गयी और न ही किसी महिला को नौकरी लगी और न ही कोई लैटर मिला। 26 मार्च को उक्त पवन शर्मा से जब रुपये वापस मांगे तो उसने रुपये हड़पने की बात कहते हुये शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने पवन शर्मा पुत्र अशोक शर्मा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4), 316 (2), 351 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

शिकायती पत्र में सांसद का नाम, एफआईआर में गायब

ईडी का दुरुपयोग कर रही केन्द्र सरकार : कांग्रेस कांग्रेसियों ने किया जोरदार प्रदर्शन

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

ललितपुर। केन्द्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर जबरन सम्पत्तियों को सीज करने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा.दयाराम रजक के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने घण्टाघर पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष डा.दयाराम रजक ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश

पर जनपद के कांग्रेसियों ने केन्द्र की बड़ी आलोचना करते हुये कहा कि नेशनल हेराल्ड सम्पत्ति को अवैधानिक रूप से सीज करना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। आज एजेन्सियां केन्द्र सरकार के दबाव में विपक्ष को निशाना बना रही है।

कहा कि इस अघोषित तानाशाही के विरूद्ध कांग्रेसियों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर

पूर्व सांसद प्रतिनिधि जसपाल सिंह बन्दी, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश रजक, रामनरेश दुबे, रफीक, असलम, रीतेश सिंघई, सुशील रजक, अशोक स्वर्णकार , दीपक रैकवार, हरदेव राजपूत, पंकज हुण्डैत, पूर्व प्रधान शशिकांत दीक्षित, अभिषेक सिंघई, रवि राजा, दयाशंकर रजक, मोहन सिंह चन्देल, पूर्व नगराध्यक्ष हरीबाबू शर्मा, सीताराम राय आदि मौजूद रहे।

साइबर क्राइम से पीड़ित चार व्यक्तियों के वापस कराए दो लाख 43 हजार 600 रुपये

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

चित्रकूट ब्यूरो: वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल टीम ने साइबर अपराध से पीड़ित चार व्यक्तियों के कुल दो लाख 43 हजार 600 रुपये उनके खातों में वापस कराए। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों ने स्क्रीन शेरिंग ऐप एवं एपीके फाइल को फोन में डाउनलोड कराकर साइबर धोखाधड़ी करते हुए चार व्यक्तियों के साथ दो लाख 43 हजार 600 रुपये की ठगी की थी। जिसकी शिकायत मिलने पर साइबर सेल प्रभारी निशीकान्त राय ने अपनी टीम आरक्षी सर्वेश कुमार व प्रशांत कुमार के साथ मामलों की विवेचना करते हुए चार पीड़ित व्यक्तियों के कुल दो लाख 43 हजार 600

रुपये उनके खातों में वापस कराए।

साइबर सेल प्रभारी निशीकान्त राय ने बताया कि वर्तमान समय में लोगों का समय बचाने के लिये व डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में भारत सरकार द्वारा लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग सेवा का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है। अतः ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ लेने वाले लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए साइबर सेल द्वारा लगातार जागरूक किया जाता हैं। कहा कि किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन पर तुरंत कॉल करें या विभाग के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। साथ ही अपने नजदीकी थाने के साइबर हेल्प डेस्क व जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

समाज में डॉ भीमराव अम्बेडकर के योगदान विषय पर आयोजित की गई गोष्ठी

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

चित्रकूट ब्यूरो: जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के प्रबंधन विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर गुरुवार को सामाजिक समरसता में भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर का योगदान विषय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में प्रबंधन विभाग के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भारत रत्न बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा समाज में समरसता, सर्विधान निर्माण तथा समाज में सभी वर्गों के हितों के लिए किए गए योगदान की जानकारी दी गई। इस दौरान समान नागरिक संहिता, श्रम सुधार कानून, मौलिक अधिकारों सहित अन्य अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए समाज में नए बदलाव के लाने लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्रबंधन विभाग प्रभारी डॉ दलीप कुमार, डॉ भविष्या माथुर, डॉ रवि प्रकाश शुक्ला, विनीत पाण्डेय, वर्षा वर्मा, मोहित तिवारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी डॉ रीना पाण्डेय आदि मौजूद रहे।

पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किया प्रदर्शन

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

राजापुर, चित्रकूट: पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रीय हिंदू संघटन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी हर्षिता देवड़ा को सौंपा।

इस दौरान संगठन मंत्री चन्द्रिका पाण्डेय सोनू ने कहा कि देकर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार एवं धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए। कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा करने वालों के विरुद्ध कड़ी



कार्यवाही करते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कहा कि ऐसा न होने पर संगठन के पदाधिकारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र

त्रिपाठी, कृष्णा मिश्रा, महेश कुमार, रोहित तिवारी, विजय बहादुर सिंह, स्वयं प्रकाश मिश्र, ब्रजेश शुक्ला, हर्ष गौतम, सौरभ मिश्र, राहुल शुक्ल आदि मौजूद रहे।

शादी पुरस्कार योजना के तहत दिव्यांगजन करें आवेदन

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

चित्रकूट ब्यूरो: जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रियंका यादव ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप दम्पति को प्रदान की जाती है। बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले पात्रों की विवाह के समय युवक की आयु 21-45 वर्ष व युवती की आयु 18-45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होे तथा जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र दम्पति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग चित्रकूट में भी जमा करें ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

वलस्टर बनाकर सोलर फेन्सिंग योजना का लाभ उठाए किसान

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

चित्रकूट ब्यूरो: उप कृषि निदेशक राज कुमार ने बताया कि बुन्देलखण्ड पैकेज परियोजना बुन्देलखण्ड एकीकृत कृषि (सोलर फेन्सिंग) योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड में कृषकों को अन्ना प्रथा एवं जंगली जानवरों से फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सोलर फेन्सिंग का कार्य कराया जाना है।

बताया कि इसमें न्यूनतम 10 हेक्टेयर से अधिक के फार्मर कलस्टर समूह का गठन कर कलस्टर के लिए अनुमानित कम्पोजिट सोलर फेन्सिंग औसतन 1500 रनिंग मीटर जिस पर कृषक समूह को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें 20 प्रतिशत कृषक अंश रहेगा। बताया कि जनपद में कुल 92 कलस्टर के लक्ष्य है। जिसमें कुल 1380 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सोलर फेन्सिंग से आच्छादित किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत तीन मॉडल से कार्य कराया जाना है। मॉडल एक में न्यूनतम 10 हेक्टेयर, ऊचाई 1.5मी. (पांच फीट), मॉडल दो में न्यूनतम 10 हेक्टेयर, ऊचाई 1.8मी. (छह फीट) व मॉडल तीन में न्यूनतम 10 हेक्टेयर, ऊचाई 2.10मी. (सात फीट) सोलर फॅन्सिंग की जाएगी। बताया कि इस योजना में कृषि वानकी/सहजन पौधा रोपड़ का कार्य खेत के चारों ओर मेडों पर कराया जायेगा। जिसमें पौधे का व्यय परियोजना से किया जायेगा। प्रति कलस्टर 500 सहजन के पौधे लगाये जायेंगे। योजना का क्रियान्वयन ग्राम/परियोजना स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें अध्यक्ष व सदस्य नामित किये जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सभी कृषक परियोजना मॉडल के अनुसार कलस्टर का गठन कर आवेदन कार्यालय उप सम्भाग कृषि प्रसार कर्वी, मऊ व कृषि भवन चित्रकूट में उपलब्ध कराए।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए परिवारों का निस्तारण करने के लिए निर्देश

पेयजल,सड़क,अतिक्रमण के उठे प्रकरण

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

खैरथल-तिजारा, 17 अप्रैल। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरुवार को जिला सचिवालय खैरथल-तिजारा के वीसी सभागार में आयोजित की गई। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 80 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने मौके पर परिवारों को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल, सीएमओ, मुख्यमंत्री जनसुनवाई प्रकोष्ठ एवं जनसुनवाईयों में प्राप्त होने वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें। अधिकारी प्रकरणों को लेकर ना बैठे, अपने क्षेत्राधिकार में नहीं होने पर उच्च स्तर पर संपर्क कर



निपटाएँ, अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर परिवारी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करें। जिला स्तरीय जनसुनवाई में भूमि पर अतिक्रमण,भूमि विभाजन,बिजली,खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने,सड़क, यातायात व्यवस्था सुधारने,पट्टा दिलाने बाबत,विभिन्न प्रकरणों की पुलिस जांच कराने तथा पेयजल समस्या सहित अन्य परिवाद प्राप्त हुए जिन पर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार,

विकास अधिकारी और सम्बंधित विभागों को परिवारों के निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने सभी परिवारियों को की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुये गुणवत्तापूर्ण प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिये। जागरूक युवा जीतेंदर कुमार ने खैरथल के मेंन बाजार के व्यापारियों ने अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया जिस पर उन्होंने नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा को तुरंत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में शहर के श्यामनगर वासियो ने उनके

वार्ड में पेयजल सप्लाई की पाइप लाइन अभी तक नहीं डाले जाने की शिकायत की वार्ड 19 निवासी समाजसेवी मेहमूद खां ने वार्ड मे पाइप लाईन डलवाने,रास्तो का निर्माण कराने,बोरिंग करवाने और बाईपास ओवरब्रिज निर्माण का कार्य शुरू करवाने की मांग की जिला कलक्टर ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत पाइप लाइन डालने के निर्देश दिए। कुछ लोगो ने बताया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर डाले प्रकरणों पर कलेक्टर के निर्देश की अधिकारी अवेहलना कर

रहे है प्रकरण जस के तस पोर्टल पर पड़े है जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, विद्युत विभाग अधिशासी अभियंता रतनलाल, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, डीएसओ राकेश सोनी, सहकारिता विभाग अधिकारी वेद प्रकाश सैनी, नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता आदेश कुमार, महिला एवं बाल विकास अधिकारी बीना गुप्ता, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हवा सिंह जाट,नोडल अधिकारी आयुर्वेदिक विभाग अजीत बालयाण,पीएचईडी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। साथ ही सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर हुई बैठक

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो। सीकर । मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा मंडल खाचरियावास की बैठक हुई। 19 अप्रैल व 21 अप्रैल को दाँतारामगढ़ के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा मंडल खाचरियावास के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान खाचरियावास मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यकताओं को जिम्मेदारी प्रदान की गई। 19 अप्रैल शनिवार को प्रातः 11:00 बजे पलसाना में राजस्थान के मुख्यमंत्री की आम सभा का कार्यक्रम होगा व सोमवार 21 अप्रैल को स्वर्गीय ईश्वर राम हिंडाला की मूर्ति अनावरण को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल



शर्मा प्रेमपुरा डांसरोली में दोपहर 12:15 बजे आएंगे। बैठक के दौरान गोविंद सिंह लांबा, बाबूलाल हल्दुनिया,हनुमान प्रसाद परसवाल,दिग्विजय सिंह, खाचरियावास मंडल अध्यक्ष सुशील कुमार शर्मा,कालूराम मेहरा,कालू सिंह करनीपुरा, दिनेश कुमावत,योगेश दाधीच, भंवरलाल झांझड़ा,माल सिंह

कांकरा,रवि पुजारी,रतनलाल शर्मा,जेपी शेषमा,जेपी हिंडाला, प्रताप सिंह शो खा व टा, र. सु. भा. टा. कुमावत,विक्रम चारण,सवाई सिंह चारण,सुरेंद्र सोनी,मुकेश चौधरी,सीताराम कुमावत कुली आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ककराना में हीरामल महाराज का वार्षिक मेला आज

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो झुंझुनूं चंवरा। ककराना के बड़वाले हीरामल महाराज का वार्षिक मेला आज शुक्रवार को भरेगा। हीरामल देवधाम के गुरुजी ख्याली राम गठीला तथा समाजसेवी शीशराम खटाणा ने बताया कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी गांव के बड़वाले देवधाम हीरामल मंदिर का वार्षिक मेला धूमधाम से भरेगा। 18 अप्रैल को दिन में भंडारे का आयोजन तथा रात्रि में गायकार प्रहलाद भट्टाणा बलेसर एवं कमलेश दायमा भजन पार्टी द्वारा भजनों की प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। भक्त प्रकाश चौहान ने बताया कि मेले में सभी दुकानदारों के लिए भोजन, पानी और बिजली की निशुल्क व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।

श्री चंद्र प्रकाश शर्मा हुए अंबेडकर सेवा पुरस्कार से सम्मानित

ब्यूरो -एनपीटी बूंदी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बूंदी द्वारा जिला स्तर पर वर्ष 2025 हेतु अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार श्री चंद्र प्रकाश शर्मा को प्रदान किया गया।श्री शर्मा विगत कहीं वर्षों से जिला बूंदी में सामाजिक उत्थान के कार्यों में जुड़े हुए हैं इनके द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों को संबल प्रदान किया जा रहा है श्री शर्मा को यह



पुरस्कार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय श्री अक्षय गोदारा जी द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंबेडकर पुरस्कार

वितरण के वक्त सामाजिक न्याय जिलाधिकारी श्री अर्पित जैन श्री विनोद नगर श्री मयंक नगर उपस्थित रहे

जम्मू एंड कश्मीर बैंक में श्रद्धालुओं ने किया हंगामा

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो, मुरादाबाद। बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए मुरादाबाद के तमाम श्रद्धालु आज जम्मू एंड कश्मीर बैंक पहुंचे। मगर वहां पर बेहतर इंतजाम ना होने पर श्रद्धालु भड़क उठे बैंक प्रबंधक पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया गुरुवार को जम्मू एंड कश्मीर बैंक की एक शाखा पर भारी भीड़ के कारण प्रभावित हुई। एक ही दिन में 600 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण कराने पहुंचे, जिससे बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गई। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण पंजीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई और

बैंक के कर्मचारियों को अतिरिक्त काम करना पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालु पंजीकरण के लिए बैंक के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। अधिकारियों ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे। जाने ये है पूरा मामला - बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए मुरादाबाद के तमाम श्रद्धालु आज जम्मू एंड कश्मीर बैंक पहुंचे। मगर वहां पर बेहतर इंतजाम ना होने पर वह भड़क उठे। बैंक प्रबंधक



पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। तमाम श्रद्धालु तड़के सुबह चार बजे ही पहुंच गए थे। दरअसल बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण जम्मू एंड कश्मीर बैंक की शाखा में होता है। इस साल की बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं का सैलाब अपना पंजीकरण करने के लिए जम्मू एंड

कश्मीर बैंक पर उमड़ पड़ा। फीस जमा होने की प्रक्रिया में देरी का आरोप-श्रद्धालुओं ने फीस जमा होने से लेकर पंजीकरण की प्रक्रिया में देरी और बैंक में बदइंतजामी का आरोप लगाकर हंगामा किया। बुधवार को जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर बाबा अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी नजर आई।

कई श्रद्धालुओं ने तड़के के चार बजे से लाइन में लगे हुए होने के बावजूद अपना काम नहीं हो पाने की बात कही। बायोमेट्रिक स्टॉफ करता है मनमानी-श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि बायोमेट्रिक करने के लिए स्टाफ आनाकानी कर रहा है। वर्षा गुप्ता, मोनिका गुप्ता, राजू, किशन कुमार, बृजेश, शालू, सदाबहार सिंह आदि ने भारी परेशानी होने की बात जाहिर की। श्री भोले भंडारी सेवा मंडल से जुड़े गुलशन मलिक ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग काफी समय से लाइन में लगे थे, मगर इसके बावजूद उनकी फीस जमा नहीं हो सकी, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश है। मलिक के मुताबिक लोगों के

पीलाजोहड़ा आश्रम नापावाली के पास विशाल 108 कुंडिया श्री राम महायज्ञ का आयोजन 12 जून से यज्ञों को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है- मदनलाल भावरिया

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो झुंझुनूं। नीमकाथाना तहसील के पास नापावाली पंचायत के नजदीक पीला जोहड़ा आश्रम पर आगामी 12 जून से विशाल 108 कुंडिया श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। विशाल 108 कुंडिय श्री राम महायज्ञ को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। यज्ञ के आयोजककर्ता महंत नरसीदास महाराज एवं मोहनदास महाराज पीलाजोहड़ा आश्रम ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 जून से आयोजित होने वाले 108 कुंडात्मक महायज्ञ को लेकर पीला जोड़ा आश्रम पर दिनांक 16 अप्रैल को धर्म सभा का आयोजन किया गया। जिसमें यज्ञ को लेकर विचार विमर्श किया गया। महंत नरसी दास महाराज एवं मोहनदास महाराज के अनुसार आगामी 20 अप्रैल रविवार को आश्रम पर यज्ञ को लेकर फिर विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें क्षेत्रीय संत एवं श्रद्धालु भाग लेंगे। 20 अप्रैल को ही धर्म सभा के दौरान



यज्ञ सेवा समिति कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। यज्ञ प्रेमी मदनलाल भावरिया ने बताया कि यज्ञ को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है। भावरिया के अनुसार यज्ञ हिंदू धर्म में एक पवित्र अनुष्ठान है। उन्होंने कहा कि यज्ञ भगवान का स्वरूप है क्योंकि यज्ञ से ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यज्ञ प्रेमी भावरिया ने बताया कि पीला जोहड़ा आश्रम धाम प्राचीन काल से ही संतों की तपो भूमि रही है। 12 जून गुरुवार को प्रातः 8 बजे महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। विशाल 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ 12 जून से 20 जून तक आयोजित होगा। 20 जून शुक्रवार को विशाल 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ की पूर्ण आहुति होगी एवं विशाल भंडारे का आयोजन

भी किया जाएगा। आश्रम पर धर्म सभा के दौरान यज्ञाचार्य डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा जसवंतपुरा बड़ी जोड़ी, आयोजककर्ता महंत नरसी दास महाराज एवं मोहनदास महाराज, सीताराम दास महाराज, चिचडोली, गोकुल, पंकज शर्मा बाड़ी जोड़ी, रामकरण व्यास खोरी, ग्राम पंचायत सरपंच घनश्याम कुड़ी, बनवारी लाल लोचीव, ओमप्रकाश जाखड़, सुरेश जाखड़, प्रवीण जाखड़, सुभाष जाखड़, प्रभु दयाल जाखड़, मोहन जाखड़ ,राजेश जाखड़, रणवीर पूर्व सरपंच ,महावीर शर्मा पूर्व सरपंच , महावीर राजू कुमावत ,बीरबल राम, सतपाल ,रामेश्वर गहलोत, मोहर सिंह ,शीशराम ओला, धर्मपाल , मोहनलाल बरबड, सुरेश जाखड़, ओमप्रकाश जाखड़, मोहर सिंह यादव, भगवान सहाय

RJ-64 से पंजीयन होंगे तिजारा- खैरथल के वाहन:परिवहन विभाग ने नए जिले को दिया नया कोड

खैरथल-तिजारा: परिवहन विभाग ने अलवर से बने नए जिले खैरथल-तिजारा को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधिनियम के तहत वाहनों के पंजीयन के लिए नया कोड फ़ख-64 जारी कर दिया है। अब खैरथल - तिजारा के वाहनों का पंजीयन इस नए कोड से होगा। जो अभी कहीं भिवाडी के कोड से तो कहीं अलवर के कोड से हो रहा था

लू-तापघात को लेकर आमजन बरतें एहतियात

लू-तापघात से बचाव हैं, बेहद जरूरी



आवश्यकता व अनुपात विकृति के कारण होते है। मस्तिष्क का एक केंद्र जो मानव के तापमान को सामान्य बनाए रखता है, काम करना छोड़ देता है। ऐसे में रोगी को तुरंत छायादार जगह पर कपड़े ढीले कर लेटा दिया जावे। रोगी के होश मे आने की दशा में उसे ठंडा पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का पन्ना दें। यदि उक्त सावधानी के बाद भी मरीज ठीक नहीं होता है, तो उसे तत्काल निकट

की चिकित्सा संस्थान ले जाया जाए। सावधानी बरतने की अपील लू एवं तापघात के दौरान आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसके तहत जहां तक सम्भव हो धूप में न निकलें, धूप में शरीर पूर्ण तरह से ढका हों। धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़ों का उपयोग करें। बहुत अधिक भीड़ व गर्म घुटन भरे कमरों

से बचें। बिना भोजन किए बाहर न निकलें। गर्दन के पिछले भाग, कान एवं सिर को गमछे या तौलिये से ढक कर ही जरूरी होने पर बाहर निकलें। रंगीन चश्मे एवं छतरी का प्रयोग करें।

गर्मी में हमेशा पानी अधिक मात्रा में पीएं एवं पेय पदार्थों जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, जूस आदि का प्रयोग करें। लू-तापघात से प्रायः हाई रीस्क श्रेणी वाले लोग जैसे कि कुपोषित बच्चे, वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं व शुगर, बीपी आदि के मरीज शीघ्र प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी जरूरत होने पर तत्काल 108 को कॉल करें या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं। नरेगा अथवा अन्य श्रमिकों के कार्यस्थल पर छाया एवं पानी का पूर्ण प्रबन्ध रखा जावे ताकि श्रमिक थोड़ी-थोड़ी देर में छायादार स्थान पर विश्राम कर सकें।

पांच बीघा गेहूं की फसल में आग से लाखों से ज्यादा का नुकसान ग्रामीणों ने पानी के टैंकर से पाया काबू



नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो, अमरोहा। हसनपुर तहसील के गांव मटीपुरा में एक किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है गुरुवार दोपहर को किसान राजू के खेत में रखे पांच बीघा गेहूं के लाक में अचानक आग लग गई आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा गेहूं जलकर राख हो गया आग पर काबू पाया -ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते मौके पर पानी का टैंकर मंगवाया और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया किसान राजू ने बताया कि इस घटना से उन्हें 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है घटना की सूचना राजस्व प्रशासन को दे दी गई है

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्य सचिव को सौंपा वेतन विसंगति दूर करने की मांग पत्र

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की समीक्षा बैठक, दिया निर्देश

एनपीटी, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र सौंप कर झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वेतन विसंगति को दूर करने का आग्रह किया गया है। संघ की अध्यक्ष रंजीता हेब्रम और महासचिव राहुल कुमार द्वारा सौंपे गये पत्र में कहा गया है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में संयुक्त सचिव स्तर के 125, अपर सचिव के 15 और विशेष सचिव के 10 पद हैं। इन पदाधिकारियों को लेवल 13 (ग्रेड पे 8700), लेवल 13 (ग्रेड पे 8700) और लेवल 13ए (ग्रेड पे 8900) का वेतनमान मिलता है। इस तरह संयुक्त सचिव से अपर सचिव के पद पर प्रोन्नति के बाद भी उन्हें वेतन वृद्धि का कोई लाभ नहीं मिलता है। इस तरह



प्रोन्नति के बाद भी वेतन वृद्धि नहीं होना मानव संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों की अवहेलना है। इसके अलावे संघ ने कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का अधिकतम वेतनमान लेवन 13 ए

(ग्रेड पे-8900) है। जबकि राज्य के कुछ अन्य सेवाओं, अभियंत्रण सेवा, चिकित्सा सेवा के अधिकारियों को लेवल 14 (ग्रेड-पे 10000) का वेतनमान मिलता है। इससे भी झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के

अधिकारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अपर सचिव एवं विशेष सचिव रैंक के अधिकारियों को लेवल 13 ए एवं 14 का वेतनमान दिया जाना चाहिए। इससे सरकार पर कोई विशेष वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। संघ का कहना है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा को पुनर्गठित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। पर कमेटी की अनुशंसा मिलने में समय लगने की सम्भावना है। इस बीच झारसे के अधिकारी रिटायर करते जा रहे हैं। वित्तीय लाभ से वंचित होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार को तत्काल वेतन विसंगति दूर करनी चाहिए।

एनपीटी, झारखण्ड के राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में झारखण्ड में कार्यरत विभिन्न इकाई यथा-झा॰स॰पु॰ / आई॰आर॰बी॰) एस॰आई॰एस॰एफ॰/एस॰आई॰आर॰बी॰ वाहिनियों की वर्तमान कार्यप्रणाली के मद्देनजर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विशेष चर्चाएं हुईं। बैठक में डॉ॰ संजय आनन्दराव लाठकर, अपर पुलिस महानिदेशक, अभियान, सुमन गुप्ता, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशि॰



एवं आधु॰, अखिलेश कुमार झा, पुलिस महानिरीक्षक, रांची, अमोल विनुकांत होमकर, पुलिस महानिरीक्षक, अभियान, ए॰ विजयालक्ष्मी, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पटेल मयूर कनैयालाल, पुलिस महानिरीक्षक,

मानवाधिकार, अनुप बिरथर, पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर, रांची भौतिक रूप से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असीम विक्रांत मिंज, पुलिस महानिरीक्षक, अप॰अनु॰वि॰ अन्य मौजूद थे।

चिकित्सकों के पैनल का निर्माण हेतु चयन समिति की हुई बैठक



एनपीटी ब्यूरो, पाकुड़ (झा॰खंड॰), बीते गुरुवार सदर अस्पताल पाकुड़ में विशेषज्ञ/ अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा के लिए चिकित्सकों के पैनल का निर्माण हेतु चयन समिति का बैठक उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। तीन विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी- स्त्री रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ ने अपनी सेवा सदर अस्पताल पाकुड़ में देने की सहमति प्रदान की है। चयन समिति के बैठक में सिविल सर्जन, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, जिला आरसीएच पदाधिकारी, जिला भीबीडी पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पाकुड़ उपस्थित रहे।

समाजसेवी शहनाज ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत, जल्द समाधान का मिला आश्वासन



महागामा(गोड्डा): प्रखंड क्षेत्र की लोकप्रिय समाजसेवी सह नेता श्रीमती शहनाज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं विकासगत मुद्दों से अवगत करते हुए मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा की। इस दौरान समाजसेवी शहनाज ने महागामा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति और महिलाओं के सर्वाधिकारण से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने समाजसेवी सह नेता शहनाज की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को उचित कार्रवाई के निर्देश देने का आश्वासन दिया। वहीं समाजसेवी शहनाज के समर्थकों की माने तो समाजसेवी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की गई ये मुलाकात न केवल महागामा प्रखंड क्षेत्र की जनता की आवाज को झारखंड सरकार तक पहुंचाने का प्रयास था, बल्कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक सार्थक कदम भी सिद्ध होगी।

झारोटेफ महागामा इकाई की हुई समीक्षा बैठक में कोषाध्यक्ष बने राजेंद्र पंडित

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

महागामा(गोड्डा): प्रखंड क्षेत्र के राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जानगर में झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्पलाइज फेडरेशन (झारोटेफ) की महागामा इकाई का समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला संयुक्त सचिव मुरारी प्रसाद शर्मा एवं संचालन जिला उपाध्यक्ष सह अनुमंडल प्रवक्ता रीतेश रंजन ने किया। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्जान हाशमी ने पूर्व में आयोजित ध्यानाकर्षण रैली की समीक्षा की एवं रैली को सफल बनाने हेतु सभी सदस्यों को बधाई दी। बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड



उपाध्यक्ष निलेश कुमार ने कहा कि अप्रैल तक सभी संकुलों में झारोटेफ की इकाई का गठन कर लिया जाएगा। वहीं प्रखंड संयुक्त सचिव नियाज अहमद ने राजेंद्र पंडित को कार्यकारी कोषाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। शहजाद अनवर ने प्रखंड स्तर पर एक आकस्मिक कोष के

कोष के गठन की बात कही तथा प्रखंड सचिव गणेश गुंजन ने आगामी कार्यक्रमों के तैयारी की रूपरेखा प्रस्तुत की। बैठक में सुनील पंडित, अंजनी चौधरी, नितेश दुबे, कमर मुस्तर, अजीमुद्दीन, कुंदन कुमार शाही, उत्तम कुमार आदि उपस्थित थे।

पोषण पखवाड़ा के तहत पोषाहार और मोटे अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी किया गया

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

पथरगामा (गोड्डा) पथरगामा प्रखंड परिसर में पोषण पखवाड़ा के तहत एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पोषाहार पैकेट और मोटे अनाज (मिलेट्स) से तैयार किए गए रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों और पौष्टिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश कुमार गौतम ने सहभागिता निभाते हुए विभिन्न व्यंजनों की जांच की और उनके पोषण मूल्य की सराहना की। उन्होंने उपस्थित सेविकाओं और



सहायिकाओं को इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को गाँव-गाँव तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। बीडीओ नितेश गौतम ने कहा कि प्रदर्शनी का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पोषण संबंधित जागरूकता फैलाना और मोटे अनाज के महत्व को

जनसाधारण तक पहुंचाना था ' मौके पर बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका प्रीति रानी, रेनू टुडू, सेविका सुवासिनी मरांडी सहायिका सुधा देवी, राजेश्वरी कुमारी, गीता देवी, सुनीता हेब्रम, तारामुनि देवी सहित अन्य कर्मी भी उपस्थित रही।

हीट स्ट्रोक के मामले में जरूरी एहतियात बरतने का दिया निर्देश

एनपीटी ब्यूरो

लिट्टीपाड़ा (पाकुड़), बीते गुरुवार को प्रखण्ड कार्यालय लिट्टीपाड़ा के सभागार में हीट स्ट्रोक एवं पेयजल समस्या समाधान हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष के साथ कार्यशाला सह बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला सह- बैठक में श्रीम ऋतु में हीट स्ट्रोक के मामले में तेजी को ध्यान में रखते हुए इसके संकेत लक्षण और बचाव के उपाय एवं पेयजल समस्याओं का निदान के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि अधिक गर्म और शुष्क हवाओं में तापमान सामान्य तापमान से अधिक होने के कारण हीट स्ट्रोक या लू लागने का असर होता है। लू मार्च से जून के बीच चलती है। लेकिन कभी-कभी इसका असर जुलाई तक भी देखने को मिलता है। लू से थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी, खूब पसीना आना, गाढ़े रंग का पेशाब, पेड़ में ऐंठन होना और शरीर में पानी की कमी की निशानी है। सभी

विद्यालय, आँगन बाड़ी केन्द्र एवं आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हीट स्ट्रोक से बचाने और स्वच्छ पीने का पानी का इन्तेजाम करने तथा ताजा भोजन कराने, अत्याधिक धूप से बचने सहित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साथ ही सभी आवासीय विद्यालय और विद्यालय सहित आंगन बाड़ी केन्द्रों और कार्यालयों में नियमित रूप से मिट्टी का घड़ा में स्वच्छ शीतल जल ढक कर रखने की बात कही। वही उन्होंने कहा कि किसी भी गांव या आंगनबाड़ी केन्द्र, विद्यालयों में पानी की आवश्यकता होने पर प्रखण्ड के सभी ग्राम पंचायतों में टैंकर उपलब्ध है। पंचायत या प्रखण्ड को सूचित करने पर ससमय पानी उपलब्ध करायी जायगी वही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लिट्टीपाड़ा के डॉक्टर शेखावत हुसैन ने बताया कि हीट स्ट्रोक सर्वाधिक शिशुओं, बुजुर्ग लोग जो अक्सर हदय, फेफड़े, गुर्दे के रोग से पीड़ित होते हैं या जो व्यक्ति धूप में शारीरिक परिश्रम या काम करते हैं। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिंकण से

बचना चाहिए। अगर गर्म मौसम में शारीरिक गतिविधियाँ करनी हैं, तो खूब सारे तरल पदार्थ पिये (जैसे पानी और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स), लेकिन शराब और कैफीन से बचना चाहिए। शीतल पेयजल का सेवन नियमित करना चाहिए। यदि अत्यधिक पसीना आता है या तबे समय तक सूर्य की रोशनी में तीव्र गतिविधि करते हैं तो शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम के साथ-साथ तरल पदार्थों की पुनःपूर्ति की आवश्यकता होती है। अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए कार्य के दौरान बार-बार ब्रेक लेना, शिर पर टोपी और हल्के रंग के हल्के, ढीले कपड़े पहनना जरूरी होता है। शिशुओं, बच्चों या पालतू जानवरों को तेज धूप में जाने से रोकने की जरूरत है। हीटस्ट्रोक से आमतौर पर लोगों को तेज बुखार, दिमाग के ठीक काम न करने के लक्षण, उल्टी, गाढ़े रंग का पेशाब, और उच्च तापमान आदि लक्षण दिखाई देने पर तुरंत प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सम्पर्क करने की सलाह दी। इस कार्यशाला में सभी विभागों यथा बाल

विकास विभाग से आंगन बाड़ी केन्द्र , जेएसएलपीएस के स्वयं सहायता समूह, मनरेगा के बागवानी सखी, मनरेगा मेट, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय लिट्टीपाड़ा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय धरमपुर (कदवा), पहाड़िया कल्याण विध्यालय धनघरा एवं धरमपुर, मॉडल स्कुल हेठबंथा, राजकीयकृत उच्च विद्यालय लिट्टीपाड़ा को प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा सकेतिक रूप से मिट्टी का घड़ा प्रदान किया गया। इस कार्यशाला सह बैठक में मुख्य रूप से पेयजल स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता रवि शंकर, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कमल पहाड़िया, प्रखण्ड कृषि सह प्रभारी कल्याण पदाधिकारी के. सी. दास, महिला पर्यवेक्षिका सोनाली, आवासीय विद्यालय के वार्डेन एवं प्रधानाध्यापक सीमा कुजूर , गुहिया पहाड़िया, सोबान सोरेन, फ्रैंक मुर्मू, प्रवाह एन.जी.ओ के प्रखंड समन्वयक शालिनी सन्नी सहित काफी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मियों सहित महिलाएं उपस्थित थे।

परिवार के सदस्यों का बॉयोमेट्रिक आधारित आधार सत्यापन संभव नहीं हो सका था, उनके लिए यह सुविधा उपयोगी साबित होगी। अब उन्हें केवल अंगुली के निशान की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आंखों की पुतली (आइरिश) की स्कैनिंग से भी केवाईसी पूरी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से वृद्ध, श्रमशील, अंगुलियों की छाप न आने वाले और अन्य बॉयोमेट्रिक नृटियों से जुझ रहे लाभुकों के लिए एक बड़ी राहत है। आपूर्ति पदाधिकारी



एनपीटी ब्यूरो लातेहार (झा॰खंड॰), लातेहार जिला के बारियातू प्रखण्ड अन्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में अब राशन कार्डधारकों के लिए आइरिश स्कैनिंग के माध्यम से ई केवाईसी कराने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके लिए सभी दुकानों के ई-पॉस मशीनों में बुधवार को आवश्यक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया हैं। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी आशिष रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार बुधवार को प्रखंड के सभी 43 जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के ई पोश मर्शिन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके माध्यम से अब तक जिन कार्डधारकों के

परिवार के सदस्यों का बॉयोमेट्रिक आधारित आधार सत्यापन संभव नहीं हो सका था, उनके लिए यह सुविधा उपयोगी साबित होगी। अब उन्हें केवल अंगुली के निशान की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आंखों की पुतली (आइरिश) की स्कैनिंग से भी केवाईसी पूरी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह सुविधा विशेष रूप से वृद्ध, श्रमशील, अंगुलियों की छाप न आने वाले और अन्य बॉयोमेट्रिक नृटियों से जुझ रहे लाभुकों के लिए एक बड़ी राहत है। आपूर्ति पदाधिकारी

ने सभी कार्डधारकों से अपील की है कि वे शीघ्र ही अपने संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से संपर्क कर आइरिश स्कैनिंग के माध्यम से ई- केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करवा लें। समय रहते केवाईसी न होने की स्थिति में भविष्य में राशन वितरण में बाधा आ सकती है। यह तकनीकी उन्नयन राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी, सुलभ और लाभुकों तक सटीक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भाजपा के अमृत पांडेय ने झामुमो नेता पर लगाया उगाही का गंभीर आरोप

एनपीटी ब्यूरो, पाकुड़ (झा॰खंड॰), भाजपा के जिला अध्यक्ष अमृत पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जम्मू पर बड़ी आरोप लगाया है गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का केन्द्रीय अधिवेशन रांची में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झामुमो नेताओं ने पाकुड़ जिले से लाखों की उगाही किया हैं। अभी- अभी झामुमो नेता के वायरल ऑडियो से यह साबित हो गया कि किस प्रकार झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के नेता सरकारी पदाधिकारियों को धमका कर पैसे की मांग कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में झामुमो नेता ने स्पष्ट कहा कि उनके वरीय पदाधिकारी का सख्त निर्देश है कि झामुमो के केन्द्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए व्यवस्था करेन। अमृत पांडेय ने बताया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हेमन्त सोरेन, सांसद विजय हंसना, विधायक स्टीफन मरांडी के इशारे पर ही पाकुड़ जिले में भ्रष्टाचार का खेल आज चरम सीमा पर है।

सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लें लाभ : विधायक डॉ.मंजू शिवाच

: 19 अप्रैल को इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज साहिबाबाद में होगा प्री-क्वालिफायर राउंड

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद 30प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में निर्माण श्रमिकों को जागरूक किये जाने एवं हितलाभ वितरण हेतु ब्लाक भोजपुर गाजियाबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुराग मिश्र, उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा की गयी।

उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन किये जाने एवं अधिक से अधिक पंजीयन कराये जाने हेतु अपील की गयी। सहायक श्रम आयुक्त वीरेन्द्र कुमार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत लाभ लिये जाने हेतु जागरूक किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी डा0



रूपाली द्वारा बोर्ड में पंजीयन कराये जाने की प्रक्रिया एवं श्रमिकों की पात्रता श्रेणी, बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को दी गयी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डा0 मंजू शिवाच द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों को सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लिये जाने के लिए समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े श्रमिक वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। विशिष्ट अतिथि सुचेता सिंह द्वारा भी कार्यक्रम में उपस्थित श्रमिकों से अधिक से अधिक

पंजीयन कराने तथा कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से अपने आस-पास के निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराने एवं योजनाओं से जागरूक करने की अपील की गयी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत-1, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत 04, कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत 05 एवं निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अन्तर्गत 02 (कुल 12) लाभार्थियों को धनराशि ₹0 8,44,000/- (आठ लाख चौवालीस हजार ₹0

मात्र) के स्वीकृति पत्र प्रदान किये गये।

कार्यक्रम में डा0 मंजू शिवाच, मा0 विधायक, मोदीनगर, सुचेता सिंह, ब्लॉक प्रमुख, भोजपुर, अनुराग मिश्र, उप श्रमायुक्त, वीरेन्द्र कुमार, सहायक श्रमायुक्त, हंस राज श्रम प्रवर्तन अधिकारी, डा0 रूपाली, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं मोहित अग्रवाल, सहायक विकास अधिकारी तथा जे0एन0राय सहायक विकास अधिकारी उपस्थित रहे। खबर संग्रह विपेश संवाददाता नरेश चंद्र द्वारा ।

कार्यक्रम के अन्त में अनुराग मिश्र, उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित निर्माण श्रमिकों से यह अपील की गयी कि यदि उन्हें पंजीकरण कराने में किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है, तो कार्यालय उप श्रम आयुक्त, लोहिया नगर, गाजियाबाद में आकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद इंजीनियरिंग (आईपीईसी) फाउंडेशन, इंडिया एक्सपोज़िशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा और एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी (अडव्व) इनोवेशन हब के संयुक्त तत्वावधान में रफ़िक्थॉन 2025र का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2025 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में भारत शिक्षा एक्सपो 2025 (सीजन 2) के दौरान किया जाएगा। इस संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आईपीईसी के निदेशक डॉ. अजय कुमार ने बताया कि रफ़िक्थॉन न केवल एक प्रतियोगिता है, बल्कि यह 'विकसित भारत 2047' के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के संकल्प का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन युवाओं को पारंपरिक करियर विकल्पों से आगे बढ़कर नवाचार और उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

इस मेगा इवेंट में आईडियाथॉन, कोडथॉन, हैकाथॉन और स्टार्टथॉन जैसे कार्यक्रमों के अलावा, टीम



बिल्डिंग वर्कशॉप, पीसीबी डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईपीआर, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी कार्यशालाएं भी होंगी। साथ ही, ड्रोन शो, रोबो रेस, रोबो वॉर्स और रोबो सॉकर जैसे तकनीकी मनोरंजन कार्यक्रम भी दर्शकों के आकर्षण के केंद्र होंगे। रफ़िक्थॉन 2025 में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागियों के लिए चार जिलों में प्री-क्वालिफायर राउंड आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक राउंड 19 अप्रैल 2025 को इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज, साहिबाबाद (गाजियाबाद) में होगा। इस राउंड में कक्षा 8 से लेकर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा व मैनेजमेंट के छात्र भाग ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी आयोजन स्थल पर सीधे आकर पंजीकरण कर सकते हैं।

आईपीईसी टीबीआई फाउंडेशन की सीईओ प्रियंका गुप्ता ने बताया कि रफ़िक्थॉन 2025 केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक व्यापक आंदोलन है। विजेताओं को न केवल पुरस्कार मिलेंगे, बल्कि उन्हें उद्योग जगत के विशेषज्ञों, निवेशकों और मेंटर्स के समक्ष अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, जो उनके विचारों को वास्तविकता में बदलने में सहायक होंगे। यह आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार, स्टार्टइनयूपी, एमएसएमई, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब, एचपी, वोल्ट पोस्ट, एडब्ल्यूएस अकादमी, टाई दिल्ली एनसीआर और टाई फाउंडर्स क्लब जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से हो रहा है। सववादात नरेश चंद्र द्वारा इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉ. अजय कुमार, प्रियंका गुप्ता, प्रो. डॉ. मीनाक्षी शर्मा, प्रो. डॉ. विजई सिंह, डॉ. पूजा त्रिपाठी, डॉ. महजबीन बानू, डॉ. तनवीर इकराम, अभिषेक कुमार, शोभना शर्मा और मीडिया हेड अजय चौधरी उपस्थित रहे।

आप नेता आशीष गर्ग के पिता बृजमोहन गर्ग की श्रद्धांजलि

समा में पहुंचे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद: शहर के उद्यमी व आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य आशीष गर्ग के पिता स्वर्गीय बृजमोहन गर्ग का विगत दिनों आकस्मिक निधन हो गया था ' आज उनकी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रामलीला कवि नगर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया स्वर्गीय बृजमोहन गर्ग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्वर्गीय बृजमोहन गर्ग जी एक संघर्षशील व एक सरल हृदय व्यक्तित्व के धनी थे ' स्वर्गीय बृजमोहन गर्ग को श्रद्धांजलि



देने विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा उद्यमी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए ' इस अवसर पर, आशीष गर्ग,कैप्टन चरित गर्ग, भारती गर्ग, पंकज जैन, डॉ गौरव चौहान,सुजाता शर्मा, संजय राघव,अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह,बृजपाल सिंह सोम, अधिवक्ता ठाकुर देवेंद्र

सिंह,आप जिला अध्यक्ष निमित यादव, अधिवक्ता मनोज त्यागी, चेतन त्यागी, मुकेश प्रजापति, डॉ अरुण सिंह, अशोक सिंह, संदीप चौधरी प्रधान, नितिन तिवारी, सजय कश्यप, विजय शर्मा, अभिषेक सीकरी, एस पी सिसोदिया आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए '



गाजियाबाद के नए पुलिस आयुक्त जे. रविन्द्र गौड़ ने दिनांक 17.04.2025 को चार्ज लिया और इसके बाद कमिश्नरेट के सभी राजपत्रित अधिकारीगणों से परिचय प्राप्त करते हुए मीटिंग की गई

बसंतराय में करोड़ों की लागत से बनने वाले सड़क और स्वास्थ्य उपकेंद्र का मंत्री संजय यादव ने किया शिलान्यास

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

बसंतराय (गोड्डा): झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सह गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव ने देर शाम बसंतराय प्रखंड में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चनाइचक से सनौर तक दूरी (4.65) किलोमीटर लागत (4 करोड़ 94 लाख) पथ का शिलान्यास शिलापट्ट का अनावरण नारियल फोडकर किया। वही प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ



इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन मद से बसंतराय प्रखंड के जहाजकीता गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया। उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण 55 लाख से कराया जाएगा। मंत्री सह गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव ने कहा कि यह इलाका पिछड़ा इलाका है लेकिन अब यह जगह सबसे

ज्यादा विकसित जगह बनेगा। उन्होंने कहा कि यहां जो आज रोड का शिलान्यास किया गया है वह काफी महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क का और उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री का सपना दिखाता है कि पिछड़े क्षेत्र में विकास की गंगा बहाना है और उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। कहा की जो वादा किया हूं

डंके की चोट पर पूरा करूंगा। उन्होंने आम जनो से समाज को बांटने वाले तथा धर्म संप्रदाय उच्च नीच जात-पात के नाम पर बरगलाने वाले लोगों से सचेत रहने को कहा। कहा अगर जनता का एजेंडा सिर्फ विकास हो जाए तो हर जनप्रतिनिधि को काम करना ही पड़ेगा। इस अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी से मंत्री का फूल माला के साथ स्वागत किया। मौके पर जपि सदस्य अरशद वहाब, कांग्रेस नेता आलमगीर आलम, मुहम्मद सगीरुद्दीन, मुहम्मद शरीफ, कपूर्ती ठाकुर सहित गणमान्य उपस्थित थे।

गाजियाबाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ,पुलिस कमिश्नर सहित तीन अफसरों के तबादले

नेशनल प्रेस टाइम्स ,ब्यूरो।

गाजियाबाद। ज़िले में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल करते हुए नई तैनाती दी गई सबसे बड़ा बदलाव पुलिस महकमों में देखने को मिला गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा का तबादला कर दिया गया है उनकी जगह अब आगरा के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ गाजियाबाद की कमान संभालेंगे। दूसरे बदलाव में पीसीएस अधिकारी निखिल चक्रवर्ती को

एसडीएम मोदीनगर के पद पर नियुक्त किया गया है



इसके अलावा लोनी में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट न्यायिक पद पर आईएसएस अधिकारी पूजा गुप्ता की नियुक्ति की गई है इसी के साथ पीसीएस अधिकारी अजीत सिंह को अपर नगर मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है ज़िले में हुये इन बड़े बदलाव से माना जा रहा है कि ज़िले की शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकेगा

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए बीएसए को सौंपा झापन

जीपीए को बीएसए ने आरटीई के सभी बच्चों का दाखिला कराने के लिए किया आश्वस्त

नेशनल प्रेस टाइम ब्यूरो

गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा आरटीई के अंतर्गत चर्चानित 6306 बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाने और आरटीई के दाखिले नहीं लेने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से वार्ता कर आरटीई के अभिभावकों की पीड़ा से अवगत कराया गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी और सचिव अनिल सिंह ने बताया कि आज हमने सभी बिंदुओं से अवगत कराते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बताया कि 1.जिले में 1206 स्कूलों में 19666 आरटीई की दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह की सीटों के सापेक्ष दिसंबर से मार्च माह तक चली चार चरणों की प्रक्रिया के तहत 6306 बालक बालिकाओं का चयन हुआ है जिसके बाद भी जिले में 13360 से ज्यादा सीटे रिक्त रह गई है जिन पर तत्काल प्रभाव से आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब अभिभावकों के बच्चों का आवेदन कराया जाए जिससे कि जिले के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा का



मौलिक अधिकार मिल सके 2.दिसंबर माह से प्रारंभ हुई चार चरणों की प्रक्रिया के दौरान दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के अंतर्गत चयनित 6306 बालक बालिकाओं को निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नहीं दिया गया है पूर्व वर्षों की तरह जब इस वर्ष भी अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला स्कूल कराने के लिए स्कूल जा रहे है तो कुछ स्कूलों का कहना है कि उनके यहां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सूची नहीं आई है, कुछ स्कूल कहते हैं कि उनके यहां सीटे फूल हो गई है एवं अनेकों स्कूलों द्वारा अभिभावकों को शोषण करने के लिए बैंक स्टेटमेंट, फार्म 26 अ

सहित अनावश्यक कागजात मांग कर आरटीई अधिनियम के नियमों की धजियां उड़ाई जा रही है जिसकी शिकायत अभिभावकों द्वारा बीएसए कार्यालय में की गई लेकिन अभी तक ऐसे स्कूलों मांगने पर कोई कार्यवाई सुनिश्चित नहीं की गई है अतः गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन आपसे निवेदन करती है कि शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी चयनित बच्चों का दाखिला सुनिश्चित किया जाए और स्कूलों द्वारा अनावश्यक कागजात मांगने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए एवं आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाए ।

जिले में आरटीई के कुल स्कूल 1206 जिले में आरटीई की कुल सीटे 19666 चार चरणों में आवंटित सीटे चरण पहला चरण 3035 दूसरा चरण 1743 तीसरा चरण 984 चौथा चरण 544 कुल चयनित 6306 कुल सीटे 19666 रिक्त बची सीटे 13360

3.जिले के निजी स्कूलों द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 का उल्लंघन करते हुए दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के अंतर्गत चयनित बालक बालिकाओं के घर स्कूल स्टाफ को भेजकर जांच एवं वेरिफिकेशन कराई जा रही है जिस पर जिले के सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी कर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी अतिआवश्यक है जिससे कि आरटीई के अंतर्गत चयनित किसी भी गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों के निजता का अधिकारो का हनन निजी स्कूलों द्वारा न किया जा सके 4.जिले में लगभग 1750 से

जा सकता है जो वर्तमान में 19666 है 5.अगले वर्ष शिक्षा सत्र 2026/27 के लिए जिले के सभी जोन के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सीटों की मैपिंग ठीक प्रकार सुनिश्चित की जाए जिससे कि स्कूलों में आरटीई की सीटों की संख्या बढ़ सके और कोई भी स्कूल सीटे फूल होने का बहाना न बना सके गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आश्वस्त किया है कि आरटीई के अंतर्गत चयनित आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब अभिभावकों के बालक बालिकाओं की शिक्षा के मौलिक अधिकारों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी बिंदुओं का संज्ञान लेकर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और आरटीई अधिनियम 2009 का उल्लंघन कर बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाई सुनिश्चित की जाएगी इस मौके पर सीमा त्यागी, अनिल सिंह, धर्मेन्द्र यादव, विवेक त्यागी, मनीष कुमार , नवीन , राहुल कुमार , मीनू, ज्योति , राजकुमार , आदि अनेकों आरटीई के अभिभावक मौजूद रहे